छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 179 ■ अम्बिकापुर, शुक्रवार 10 जुलाई 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

सीएमएचओ के आदेशों की अवहेलना करके चिकित्सकीय कार्यों से बनाई दूरी

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने संभागीय संयुक्त संचालक का ध्यानाकर्षण कराया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा के प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. राहुल कुमार कुशवाहा पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सरगुजा ने चिकित्सकीय सेवाओं से दूरी बनाकर रखने और अपना कार्यालय दरिमा की जगह फुंदुरडिहारी, अंबिकापुर में संचालित करने का आरोप लगाया है। संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के नाम 8 जुलाई को प्रेषित किये गये पत्र में संघ ने संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है।

संघ के जिला अध्यक्ष धनेश प्रताप सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि डॉ. कुशवाहा को वर्ष 2024 में दरीमा सीएचसी का प्रभार दिया गया था, लेकिन तब से आज तक न तो उन्होंने दरिमा में एक भी दिन ओपीडी, आईपीडी में इमरजेंसी सेवा दी और न ही कार्यालयीन कार्य किया। आरोप है कि सीएचसी दरिमा का कार्यालय फुन्दुरडिहारी, अंबिकापुर में संचालित किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है। इस मामले में बीते 29 मई को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सरगुजा के द्वारा पत्र जारी करके इन्हें प्रशासनिक एवं ओपीडी के दायित्वों का दरिमा में रहकर निर्वहन करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन इन्होंने इस आदेश का आज पर्यंत पालन नहीं किया है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने संभागीय संयुक्त संचालक से जनहित और विभाग हित में तत्काल उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल मामले में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की उम्मीद है।

सीएमएचओ ने भी दिया था निर्देश

पत्र में जिक्र है कि सीएमएचओ सरगुजा ने कलेक्टर के निर्देश पर 29.05.2026 को पत्र जारी करके डॉ. कुशवाहा को दरिमा में कार्यालय स्थापित कर ओपीडी की सेवा शुरू करने का आदेश दिया था, साथ ही चेतावनी दी थी कि, आदेश नहीं मानने पर वेतन रोकने की कार्रवाई होगी। संघ का कहना है कि सीएमएचओ के आदेश के बाद भी डॉ. कुशवाहा ने न कार्यालय स्थानांतरित किया और न मरीजों का इलाज शुरू किया। इसे उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और तानाशाही रवैया बताया गया है।

सीएम हेल्पलाइन नंबर में भी शिकायत

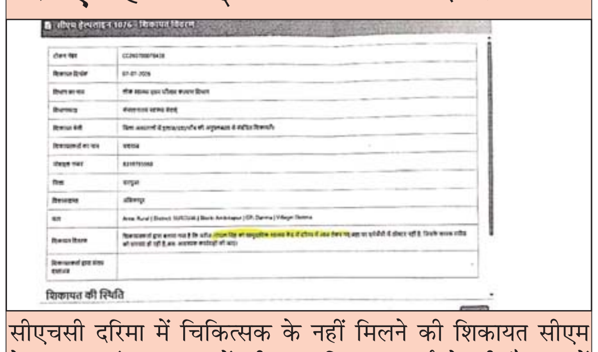

सीएचसी दरिमा में चिकित्सक के नहीं मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 में भी एक शिकायतकर्ता ने की है। इसमें उल्लेख है कि, मरीज गोपाल सिंह को 7 जुलाई को स्वास्थ्य केन्द्र दरिमा में लेकर गये, यहां पर इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं हैं। इसके कारण मरीज को समस्या हो रही है। अतः आवश्यक कार्रवाई की जाये।

सीएमएचओ कार्यालय से जारी आदेश

सीएमएचओ कार्यालय से 29.05.2026 को जारी पत्र में डॉ. राहुल कुमार कुशवाहा को संबोधित करते हुये उल्लेख किया गया है कि, आप अपने प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ ओपीडी सेवायें प्रदान नहीं कर रहे हैं, जबकि चिकित्सकीय सेवाओं का सुचारू संचालन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे डॉ. कुशवाहा को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ सीएचसी दरिमा में अपना कार्यालय एवं मुख्यालय निर्धारित करते हुये ओपीडी सेवा नियमित रूप से दें, अन्यथा वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। यह भी सुनिश्चित करने कहा गया है कि, प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के कारण रोगियों के उपचार एवं ओपीडी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 2.30 करोड़ रुपये से अधिक प्रोत्साहन पारिश्रमिक

ऑनलाइन माध्यम से 8 से 13 जुलाई तक 16,981 संग्राहकों को किया जायेगा भुगतान

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के निर्देशानुसार तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 के अंतर्गत पात्र संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 जुलाई को सहकारिता सप्ताह एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सरगुजा अंतर्गत पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहकों को निर्धारित समय-सीमा में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सरगुजा ने बताया कि जिला यूनियन अंतर्गत संचालित 06 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कुल 16,981 पात्र संग्राहकों को 2 करोड़ 30 लाख 61 हजार 50 रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि वितरित की जाएगी। यह राशि 13,761.590 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण के आधार पर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि भुगतान कार्य ऑनलाइन एमएफबी कलेक्शन एंड पेमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर के माध्यम से 8 जुलाई से 13 जुलाई तक ऑनलाइन किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वितरण संबंधी जानकारी राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

समितिवार भुगतान की जाने वाली राशि

समितिवार वितरण के अनुसार केदमा समिति के 2,073 संग्राहकों को 28,09,597 रुपये, कमलेश्वरपुर समिति के 1,527 संग्राहकों को 2,74,018 रुपये, लखनपुर समिति के 4,211 संग्राहकों को 20,21,194 रुपये, उदयपुर समिति के 2,824 संग्राहकों को 31,90,545 रुपये, डांडगांव समिति के 2,955 संग्राहकों को 95,84,633 रुपये तथा रीखी समिति के 3,391 संग्राहकों को 51,81,063 रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि प्रदान की जाएगी।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

तेन्दूपत्ता संग्रहण से जुड़े पात्र संग्राहकों को मिलने वाली यह प्रोत्साहन राशि वनांचल क्षेत्रों के परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे संग्राहकों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रबंध संचालक ने बताया कि प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भुगतान प्रक्रिया की सतत निगरानी करते हुए निर्धारित अवधि में प्रत्येक पात्र हितग्राही तक राशि पहुंचे, निर्देशित किया गया है।

फर्जी दस्तावेजों के सहारे लकड़ी तस्करी, वन विभाग ने ट्रक जब्त किया

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। वन संपदा की सुरक्षा के लिए बलरामपुर वन मंडल के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वन मंडलाधिकारी आलोक बाजपेयी के निर्देशन एवं रामानुजगंज वन परिक्षेत्र अधिकारी डॉ. दिलरुबा बानो के नेतृत्व में गुरुवार को तड़के वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परिवहन में लगी भारी मात्रा में लकड़ी से लदे ट्रक को जब्त किया है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे कन्हर बेरियर रामानुजगंज में नियमित जांच के दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 15 ईडी 9966 को रोका गया। दस्तावेजों की जांच में गंभीर अनियमितता सामने आने पर ट्रक की तलाशी ली गई। जांच में गम्हार, जामुन एवं नीलगिरी प्रजाति की कुल 89 नग लकड़ियां (22.074 घन मीटर) फर्जी दस्तावेजों के सहारे परिवहन करते पाई गईं। वन परिक्षेत्र अधिकारी डॉ. दिलरुबा बानो ने बताया कि मामले में अपराध क्रमांक 2197/2/09 दर्ज कर लकड़ी से लदे ट्रक को जब्त करते हुए चोरपहरी डिपो में सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ट्रक अनूपपुर से बिहार की ओर जाना पाया गया है। पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है। दस्तावेजों की सत्यता सहित परिवहन से

जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कार्रवाई में वनपाल दयाशंकर, विजय बर्मन, सूसना भगत, राजनाथ, पिंटू मालाकार, मंगल राम, निखिल सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रभावी कार्रवाई की सराहना

वन परिक्षेत्र अधिकारी डॉ. दिलरुबा बानो के नेतृत्व में की गई इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है। लगातार सख्ती और सतर्कता के चलते वन विभाग अवैध लकड़ी परिवहन तथा वन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफल हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

महिला स्व-सहायता समूह की राशि में अनियमितता पर एफआईआर दर्ज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी मिथलेश पैंकरा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला समूह के नाम पर 6 लाख रुपये निकालने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच हेतु समिति गठित की गई थी। जांच समिति ने पाया कि ग्राम पंचायत कोसगा की सक्रिय महिला अंबानी महतवार के द्वारा आम महिला स्व सहायता समूह से 1.20 लाख एवं अनमोल आजीविका ग्राम संगठन से 5.99 लाख कुल 7.19 लाख रुपये नियम विरूद्ध लिया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अंबानी महतवार को 10 दिवस के भीतर ब्याज सहित संपूर्ण राशि संबंधित संगठनों को वापस करने हेतु निर्देशित किया गया, किंतु उक्त अवधि में इनके द्वारा राशि वापस नहीं की गई। राशि वापस नहीं करने के कारण लखनपुर के चारपारा के कोसगा की निवासी पवित्री चौधरी के द्वारा थाना लखनपुर में उनके साथ हुए फर्जीवाड़े के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार अबांनी महतवार लगभग 1 वर्ष से स्व सहायता समूहों का पैसा अपने पास रखी है एवं पैसा वापस नहीं कर रही हैं। इसके आधार पर थाना प्रभारी लखनपुर के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 2023 की धारा 318 (4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समस्त मैदानी अमलों एवं स्व सहायता समूहों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी संगठन में किसी भी स्तर पर कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आईजी के निर्देश पर सरगुजा पुलिस अलर्ट, किरायेदारों को खंगाल रही पुलिस

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बस-ट्रक में काम करने वालों पर भी है नजर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर में बाहरी राज्यों से आकर किराये के छोटे-बड़े मकानों में रह रहे लोगों की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज ने समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आ रही खबरों और वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे के द्वारा इस संबंध में कराये गये ध्यानाकर्षण के बाद घुसपैठियों और संदिग्ध किरायेदारों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिये हैं, इसके पालन में संदिग्ध व्यक्तियों, मुसाफिरों की जांच, पहचान एवं निर्वासन हेतु सघन जांच अभियान गुरूवार को चलाया गया।

जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत एवं सुदृढ़ करने, अपराधों की रोकथाम सहित नियंत्रण करने की दिशा में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के निर्देश पर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बाहरी प्रांतों से आये एवं वर्तमान में जिले में निवासरत व्यक्तियों की जांच, पहचान कर मुसाफिरी दर्ज करना शुरू कर दिया है। थाना व चौकी प्रभारियों को संदिग्धों के विरुद्ध सख्ती से वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके पालन में पुलिस टीमों ने किराए में निवासरत व्यक्तियों, निचली बस्तियों, अंदरूनी कालोनियों, पान ठेला, गुमटी संचालकों, होटलों एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में बाहर से आकर काम कर रहे व्यक्तियों, बस-ट्रक संचालकों के चालक, कंडक्टर, क्लीनर एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों में कार्यरत व्यक्तियों की जांच करके संबंधितों का पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज देखा। मौके पर पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जांच परख की गई। पुलिस टीम ने प्राप्त पहचान पत्रों का भौतिक सत्यापन करके मकान मालिकों, व्यवसायिक संस्थानों के संचालकों को कार्यरत व्यक्तियों एवं किरायेदारों से संबंधित जानकारियों को थाने में प्रस्तुत करने कहा गया। बस-ट्रकों में कार्यरत व्यक्तियों की बारीकी से जांच की गई। पुलिस टीम ने थाना अंतर्गत विभिन्न होटल, ढाबा की चेकिंग कर संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की, साथ ही मकान मालिकों एवं होटल संचालकों को किसी किरायेदार अथवा होटल में ठहरे व्यक्तियों के संदिग्ध आचरण पर इसकी जानकारी सरगुजा पुलिस के संबंधित थाने या हेल्पलाइन नंबर पर देने की समझाइस दी गई।

125 मकानों, व्यवसायिक संस्थानों की जांच

सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस टीम ने लगभग 125 मकानों, व्यवसायिक संस्थानों, बस ट्रक संचालकों के यहां कार्यरत एवं निवासरत करीब 450 व्यक्तियों के पहचान पत्र का सत्यापन किया। सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से आपके आसपास अवैध रूप से रह रहे, छिप कर रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों/मुसाफिरों के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर उक्त सूचना को त्वरित सरगुजा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9479193599 अथवा डॉयल 112 में देने कहा है, जिससे सूचना की तस्दीकी एवं वैधानिक कार्रवाई पुलिस टीम कर सके। सूचना देने वाले की जानकारी पुलिस टीम द्वारा गोपनीय रखी जायेगी।

पुलिस टीम घर-घर कर रही पूछताछ

पुलिस टीम के द्वारा किरायेदार कहां से आया है और क्या काम करता है, मकान मालिक ने थाने में सूचना दी है या नहीं, जानकारी लेकर इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी सहित वास्तविक पहचान से संबंधित दस्तावेज की जांच कर रही है। संदेह होने की स्थिति में इनके मूल निवास से संबंधित थाने की पुलिस से संपर्क करके कोई अपाराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, इसकी भी जानकारी हासिल कर रही है।

डीजीपी ने उप निरीक्षकों का पदोन्नति सूची जारी किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2026 की योग्यता सूची जारी कर दी है। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के हस्ताक्षर से 8 जुलाई को जारी आदेश में सरगुजा संभाग से 7 उप निरीक्षकों के नाम शामिल हैं।

सरगुजा संभाग के सरगुजा से विजय कुमार कैवर्त, अश्वनी दीवान, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला से ओम प्रकाश पटेल, विरासत कुजूर, आराधना बनोदे, जशपुर जिला से अशोक कुमार यादव, कोरिया जिला से आनन्द सोनी उपनिरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। आदेश में उल्लेख है कि, यह योग्यता सूची प्रकाशन दिनांक से 18 माह तक या नई सूची जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। यदि सूची में शामिल किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित है और बड़ी सजा होती है, तो उसका प्रकरण पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा। पदोन्नति के बाद भी कोई प्रतिकूल जानकारी मिलने पर पदोन्नति निरस्त की जा सकती है। सूची के जारी होने के बाद इन्हें जल्द ही निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिलेगी।

निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने 8 जुलाई को पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय के बाद निरीक्षकों के अस्थायी तबादले का आदेश जारी किया है। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के हस्ताक्षर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सरगुजा रेंज में फेरबदल करते हुये सरगुजा से निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी को जिला सुकमा, दुर्गेश्वरी चौबे को रायपुर ग्रामीण, सूरजपुर जिला से राजेन्द्र साहू को जिला कांकेर, मनी प्रसाद राजवाड़े को जिला कोण्डागांव, नरेन्द्र कुमार मिश्रा को जिला कांकेर, नीलिमा तिर्की को जिला कांकेर, विमलेश दुबे को जिला बीजापुर, कोरिया जिला से हेमंत कुमार अग्रवाल को जिला बस्तर, विनोद पासवान को जिला नारायणपुर, एमसीबी जिला से कमलेश देवांगन को जिला बस्तर, जशपुर जिला से अशोक कुमार शर्मा को जिला दंतेवाड़ा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला से निरीक्षक जन्मेजय पांडेय को जिला बालोद, दिव्यकांत पांडेय को जिला मुंगेली स्थानांतरित किया गया है। यह फेरबदल कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

रनपुर खुर्द स्थित 'माता नाथल देवी मंदिर' का होगा जीर्णोद्धार व भव्य निर्माण

बेनीपुर ग्राम की धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए गठित हुई समिति

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सद्भावना ग्राम तकिया से लगे ग्राम बेनीपुर, पंचायत रनपुर खुर्द स्थित प्राचीन आस्था केंद्र माता नाथल देवी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं भव्य निर्माण के लिए माता नाथल देवी मंदिर निर्माण एवं जीर्णोद्धार समिति का गठन किया गया है।

समिति के अध्यक्ष गौटिया अर्जुन पटेल ने कहा कि बेनीपुर एक ऐसा सद्भावना ग्राम है, जहां धार्मिक और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। यहां स्थित माता नाथल देवी का मंदिर क्षेत्र की प्राचीन आस्था का केंद्र है। परंपरा के अनुसार चैत्र एवं शारदीय नवरात्र में मां महामाया की पूजा-अर्चना, माता नाथल देवी के स्थल से चुनरी प्रस्थान होने के बाद ही संपन्न माना जाता है। इस मंदिर में आज भी बैगा परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना की जाती है, बैगा गुनिया के पूजा-अर्चना और मंत्रोचार में माता नाथल देवी का नाम अवश्य रूप से लिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्राचीन धरोहर का संरक्षण और विकास करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अध्यक्ष अर्जुन पटेल ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन, जनप्रतिनिधियों के सहयोग तथा जनभागीदारी से इस पवित्र स्थल का जीर्णोद्धार कर इसे एक सुसज्जित और व्यवस्थित धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेनीपुर, पंचायत रनपुर खुर्द स्थित माता नाथल देवी मंदिर के प्राचीन अवशेष आज भी मौजूद हैं तथा परिसर की बाउंड्री वॉल भी निर्मित है। वर्षों से श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए आते रहे हैं। प्राचीनकाल से बैगा, गुनिया एवं ग्रामीण इस स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते रहे हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार ग्राम्य पूजा-पद्धतियों में माता कामाख्या के स्वरूप माता नाथल देवी की पूजा का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने कहा कि बेनीपुर की पहचान धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर के जीर्णोद्धार और मंदिर निर्माण का कार्य समाज के सभी वर्गों के सहयोग से शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

पर्यटन, संस्कृति मंत्री ने दी 5 लाख की स्वीकृति

मंदिर परिसर के विकास के लिए पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार की विचारधारा केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन को भी समान महत्व देती है।

समिति की संरक्षक दिव्या, जितेंद्र और अध्यक्ष अर्जुन पटेल

समिति की संरक्षक जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया व जितेंद्र सिंह सोनपुर, अध्यक्ष गौटिया अर्जुन पटेल, उपाध्यक्ष सतीश यादव तथा सचिव हरिशंकर बनाए गए हैं। सदस्यों में ननका बैगा, पंडा ललन प्रसाद, चंदर यादव, सुखलाल रजवाड़े, राजू यादव, भदर यादव, धनसी, राम आशीष, डिलेश्वर पैकरा, ललित राजवाड़े, नंदकेश्वर राजवाड़े, बुधनराम पैकरा, बरन राम, ननका यादव, कुमार राम, कन्हैयालाल, ननका सरपंच, रामकुमार यादव, कृष्णा यादव, मनोहर राम, चंभूलाल, रामनारायण, हरिप्रसाद, बद्रीनारायण, नरेश राम, छत्रपाल सिंह, शिवचरण पावले, नानसाय, सीताराम, चंद्रदेव, विजय मानिकपुरी, केशव प्रसाद तथा बालेश्वर रजवाड़े शामिल हैं।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026
ISO 9001: 2015 CERTIFIED
बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।
डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद
समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा
बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

ग्रामीण विकास, डेयरी और स्वरोजगार से जनजातीय क्षेत्रों को मिलेगी नई पहचान : कृषि मंत्री

★ धरती आबा अभियान में जनजातीय क्षेत्रों को विकास की सौगात ★ 8 करोड़ से अधिक रुपये की विकास परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास ★ नैनो यूरिया के उपयोग और फसल विविधिकरण अपनाने का किया आह्वान

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि, आदिम जाति विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास विभाग एवं कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8 करोड़ 17 लाख 67 हजार की राशि के 4 विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिकांश पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा शेष महत्वपूर्ण कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मकरो पीडब्ल्यूडी रोड, परसुवार पीडब्ल्यूडी रोड से करीचल गली, भैरोपुर पीएमजीएसवाई रोड से कोड़ाखूपारा तथा भैरोपुर पीडब्ल्यूडी रोड से चेमी-चबनपुर सहित अनेक सड़क निर्माण कार्य करोड़ों रुपये की लागत से स्वीकृत किए गए हैं। इनमें कुछ सड़कें तकनीकी कारणों से वर्षों से लंबित थीं, जिन्हें भारत सरकार के स्तर पर विशेष प्रयास कर स्वीकृति दिलाई गई। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक लोगों की पहुंच आसान बनेगी।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि क्षेत्र में कॉलेज भवन, थाना एवं चौकी के निर्माण कार्य भी स्वीकृत हो चुके हैं। भूमि संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होते ही कॉलेज भवन का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बलरामपुर जिले को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की डेयरी विकास योजना से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। प्रारंभिक चरण में रामचंद्रपुर एवं बलरामपुर विकासखंड में दूध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी गतिविधियों से किसानों, महिलाओं और युवाओं की आय में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मंत्री श्री नेताम ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं एवं ग्रामीणों से डेयरी, बकरी पालन, देसी एवं कड़कनाथ मुर्गी पालन तथा सुअर पालन जैसे आजीविका आधारित व्यवसाय अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने किसानों से मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए धान पर पूर्ण निर्भरता कम करने तथा मक्का, अरहर, उड़द, तिल सहित कम पानी में तैयार होने वाली दलहनी एवं तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप फसल विविधीकरण अपनाकर किसान संभावित नुकसान से बच सकते हैं।

मंत्री श्री नेताम ने किसानों को नैनो यूरिया के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया के प्रयोग से उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर वैज्ञानिक खेती करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना नहीं, बल्कि किसानों, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराकर जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन के प्रयासों से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से निश्चित ही जिले के दूरस्थ गांवों में विकास को नई गति मिलेगी और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8 करोड़ 17 लाख 67 हजार की राशि के 4 कार्य जिसके अंतर्गत पीडब्ल्यूडी रोड से मकरो तक 1.29 किलोमीटर सड़क का निर्माण 111.68 लाख रुपये, परसुवार पीडब्ल्यूडी रोड से कर्री चलगली तक 3.10 किलोमीटर सड़क का निर्माण 272.84 लाख रुपये, पीडब्ल्यूडी रोड से कोड़ाखूपारा तक 1.90 किलोमीटर सड़क का निर्माण 203.55 लाख रुपये तथा पीडब्ल्यूडी रोड से चेमी-चमनपुर तक 1.40 किलोमीटर सड़क का निर्माण 229.60 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।

कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री कृष्णा गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कार्यपालन अभियंता पीएमजीएसवाई श्री सच्चिदानंद कांत, जनपद सीईओ श्री दीपराज कांत, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

सिकल सेल रोग से प्रभावित बच्चों और परिजनों को उपचार एवं देखभाल की दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय सिंह के नेतृत्व में जिले में सिकल सेल रोग से प्रभावित बच्चों एवं उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने, नियमित उपचार के प्रति जागरूक करने तथा आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा यूनिसेफ फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से जिला चिकित्सालय, बलरामपुर में रोगी सहायता समूह की बैठक आयोजित की गई।

कार्यक्रम में सिकल सेल से प्रभावित 51 बच्चों एवं 38 अभिभावकों सहित स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ, एकम फाउंडेशन सहित 104 प्रतिभागी शामिल हुए। बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सिकल सेल रोग की समय पर पहचान, नियमित स्वास्थ्य जांच, उपचार, संक्रमण से बचाव, संतुलित पोषण, पूर्ण टीकाकरण तथा नियमित फॉलो-अप के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर जांच एवं निरंतर उपचार से रोग के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम कर प्रभावित बच्चों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान किया जा सकता है। इस दौरान विवाह पूर्व सिकल सेल जांच के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

संवादात्मक सत्र में अभिभावकों ने बच्चों के उपचार एवं देखभाल से जुड़े अपने अनुभव और समस्याएं साझा की। विशेषज्ञों ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक लैब जांच, रेफरल सुविधाओं तथा चिकित्सकीय परामर्श की जानकारी दी और नियमित उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की अपील की।

कार्यक्रम में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. अनुज टोप्पो, डॉ. साकेत गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष जायसवाल, डॉ. शांति नंदन, एनवीबीडीसीपी सलाहकार श्री दिव्य किशोर गुप्ता तथा बीपीएम श्री नेत्र प्रकाश सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को सिकल सेल रोग के प्रभावी प्रबंधन एवं शासन द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्रदान की।

घर से नाराज होकर निकले सेवानिवृत्त कालरी कर्मी की मौत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत केशवनगर पटेलपारा निवासी एक सेवानिवृत्त कालरी कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में शव घर से करीब 4 किलोमीटर दूर एक राइस मिल के पास पाया गया है। मृतक द्वारा जहर सेवन की बात कही जा रही है। बिश्रामपुर पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत केशवनगर पटेलपारा निवासी सेवानिवृत्त कालरी कर्मी 70 वर्षीय भरत यादव बुधवार की शाम घर में किसी बात को लेकर हुए कहा सुनी उपरांत मोटरसाइकिल लेकर घर से दोपहर 3.30 बजे निकले थे। सेवानिवृत्त कालरी कर्मी का शव घर से करीब 4 किलोमीटर दूर गांव के एक राइस मिल के समीप आज मिला है।

पुलिस द्वारा मामले में फिलहाल जहर सेवन कर आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है,जबकि वास्तविक स्थिति पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने बताया कि मृतक का मोटरसाइकिल फिलहाल नहीं बरामद हो सका है। जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य और बाल रोगों पर जागरूकता बढ़ाने पत्रकारों हेतु क्षेत्रीय संवाद एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय सिंह के नेतृत्व में जिले में स्वास्थ्य संबंधी जनजागरूकता को सशक्त बनाने तथा शासन की स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावी जानकारी आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूनिसेफ छत्तीसगढ़ एवं एमसीसीआर ट्रस्ट के सहयोग से हॉटल सत्यम इन में पत्रकारों के लिए क्षेत्रीय संवाद एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सिकल सेल रोग तथा बच्चों में गैर संचारी रोगों पर संवेदनशील एवं तथ्यपरक पत्रकारिता की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में जिले के लगभग 39 पत्रकारों ने सहभागिता की। विशेषज्ञों ने सिकल सेल रोग, बच्चों में टाइप-1 मधुमेह, जन्मजात हृदय रोग तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते हुए कहा कि समय पर पहचान, नियमित जांच एवं उपचार से गंभीर बीमारियों की रोकथाम और बच्चों को स्वस्थ जीवन प्रदान किया जा सकता है। साथ ही शासन द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं योजनाओं की भी जानकारी साझा की गई।

विशेषज्ञों ने कहा कि मीडिया समाज में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। तथ्यात्मक एवं जनहितकारी समाचारों के माध्यम से लोगों को समय पर जांच, उपचार, पूर्ण टीकाकरण, पोषण, एनीमिया नियंत्रण तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा सकता है। विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य संदेश पहुँचाने में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम में सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग, बच्चों में टाइप-1 मधुमेह के शुरुआती लक्षणों की पहचान, जन्मजात हृदय रोग से प्रभावित बच्चों के शीघ्र उपचार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी तथा समुदाय आधारित स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य विभाग, मीडिया एवं समुदाय के बीच बेहतर समन्वय को जनस्वास्थ्य सुधार की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पत्रकारों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य विषयों पर जिम्मेदार एवं तथ्यपरक समाचारों के माध्यम से आमजन को जागरूक करें, जिससे अधिक से अधिक लोग समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

इस अवसर पर यूनिसेफ की कम्युनिकेशन कंसल्टेंट सुश्री सुरभि शुक्ला, हेल्थ ऑफिसर डॉ. श्वेताभ त्रिपाठी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. गजेंद्र सिंह, डॉ. डी. श्याम कुमार एवं एमसीसीआर ट्रस्ट की टीम ,स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य दल, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

नाबालिग सहित आरोपी को नोएडा से किया गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। सोशल मीडिया एकाउंट के जरिए हुई दोस्ती के बाद चौदह वर्षीय नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर बीस दिवस पूर्व भगा ले जाने मामले में बिश्रामपुर पुलिस ने नाबालिग बच्ची सहित आरोपी प्रणव हलदार पिता निबो हलदार 21 वर्ष निवासी सरस्वती कुंड नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तरप्रदेश को नोएडा से गिरफ्तार कर अपने साथ बिश्रामपुर के आई है ।

यहां पुलिस ने नाबालिग का 183 का बयान कराया जिसमें नाबालिग द्वारा बयान में आरोपी युवक द्वारा शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की बात कही है जिसके बाद पुलिस ने दर्ज 137(2),65(1),87 बीएनएस की धारा में 65(1),87 पास्को एक्ट की धारा जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है।

सप्ताह भर से मटमैले पानी की मार झेल रहे कालोनीवासी

एसईसीएल कॉलोनियों में दूषित जलापूर्ति से बढ़ा बीमारी का खतरा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों में पिछले करीब एक सप्ताह से बिना समुचित फिल्ट्रेशन के मटमैले और दूषित पानी की आपूर्ति होने से हजारों कॉलोनीवासी गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में गंदे पानी की लगातार आपूर्ति ने लोगों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। रहवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो जलजनित बीमारियों का बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है।

कॉलोनीवासियों के अनुसार नलों से आने वाला पानी इतना गंदा और मटमैला है कि उसका उपयोग पीने की बात तो दूर, हाथ-मुंह धोने, स्नान करने और दैनिक घरेलू कार्यों के लिए भी मुश्किल हो गया है। कई घरों में लोग मजबूरी में पानी को लंबे समय तक जमाकर या छानकर उपयोग कर रहे हैं, जबकि अनेक परिवार बाहर से पेयजल की व्यवस्था करने को विवश हैं। बरसात के दौरान दूषित पानी की आपूर्ति से डायरिया, उल्टी-दस्त, टाइफाइड, पीलिया, सर्दी-खांसी और अन्य संक्रामक रोग फैलने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक चिंता छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से

बीमार लोगों को लेकर जताई जा रही है। रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।लोगों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी कई बार फिल्टर प्लांट और संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिल रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद न तो जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ और न ही पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। इससे लोगों में एसईसीएल प्रबंधन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। रहवासियों का कहना है कि यदि फिल्ट्रेशन व्यवस्था समय पर संचालित होती, जल टंकियों की नियमित सफाई होती और पाइपलाइन का समय-समय पर रखरखाव किया जाता, तो आज ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। उनका आरोप है कि संबंधित विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

कॉलोनीवासियों ने यह भी दावा किया है कि कॉलोनी में स्थित पानी की टंकियों की पिछले लगभग दो वर्षों से समुचित सफाई नहीं कराई गई है। ऐसे में बरसात के मौसम में दूषित जलापूर्ति का खतरा और बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि जल टंकियों और पाइपलाइन की नियमित सफाई नहीं होने से पानी की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। इधर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रबंधन द्वारा फिल्टर टैंक की सफाई, जो गर्मी के मौसम में पूरी कर ली जानी चाहिए थी, अब बरसात के दौरान कराई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसी कारण फिल्ट्रेशन व्यवस्था प्रभावित हुई है और बिना पूरी तरह शुद्ध किए पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है, जिससे कॉलोनियों में मटमैला पानी पहुंच रहा है।

कॉलोनीवासियों ने एसईसीएल प्रबंधन से मांग किया है कि जलापूर्ति व्यवस्था की तत्काल तकनीकी जांच कर फिल्ट्रेशन प्रणाली को पूरी क्षमता से संचालित किया जाए, जल टंकियों एवं पाइपलाइन की व्यापक सफाई कराई जाए तथा पानी की गुणवत्ता की नियमित प्रयोगशाला जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे जनस्वास्थ्य के हित में सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कर आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे।

बिश्रामपुर व जयनगर थाना प्रभारी का जिले से बाहर हुआ तबादला

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम द्वारा कई निरीक्षकों के पदस्थापना स्थलों में परिवर्तन करते हुए दूसरे जिलों में नई पदस्थापना दी गई है। जारी आदेश में बिश्रामपुर थाना प्रभारी टीआई प्रकाश राठौर को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला एवं कुछ दिनों पूर्व ही जयनगर थाना में पदस्थ किए गए टीआई नरेंद्र कुमार मिश्रा को कांकेर जिला में पदस्थ किया गया है। बताया जा रहा है कि निरीक्षकों व उप निरीक्षकों की तबादला सूची लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, जिसमें कई निरीक्षक और उपनिरीक्षक तीन वर्ष से भी अधिक समय से जिले में पड़े हुए हैं।

अवैध उर्वरक परिवहन पर कार्रवाही, 240 बोरी जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों, अवैध उर्वरक एवं कृषि आदानों के परिवहन तथा विक्रय पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा बिना वैध दस्तावेजों के जैविक खाद का परिवहन करते पाए जाने पर एक वाहन को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 08 जुलाई 2026 को थाना प्रभारी बसंतपुर को अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर बसंतपुर में वाहन क्रमांक सीजी-04 पीयू-5217 की जांच की गई। जांच के दौरान चालक द्वारा जैविक खाद के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। थाना प्रभारी द्वारा ट्रक वाहन को अभिरक्षा में लेकर कृषि विभाग को उक्त संबंध में जानकारी दी गई। जिस पर कृषि विभाग के अमले द्वारा ट्रक वाहन में रखे उरर्वक का जांच किया गया। जांच में पाया गया कि वाहन में 240 बोरी जैविक खाद परिवहन की जा रही थी। कृषि विभाग की टीम के द्वारा नियमानुसार खाद का नमूना लेकर परीक्षण हेतु भेजा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उक्त जैविक खाद हरियाली एग्रो, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा निर्मित बताई गई है, जिसका निर्माण माह मई 2026 अंकित है।

कृषि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त उपस्थिति में उक्त वाहन को जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। इस संबंध में उप संचालक कृषि ने बताया कि उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत आगे की कार्रवाई की की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिले में किसानों के हितों की सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की जांच एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

जिला स्तरीय रोजगार मेला 13 जुलाई को, 1470 पदों पर होगी सीधी भर्ती

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बलरामपुर द्वारा 13 जुलाई 2026 (सोमवार) को प्रातः 10:30 बजे से जनपद पंचायत बलरामपुर के सभाकक्ष में एक दिवसीय विशाल एवं निःशुल्क जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में चिकित्सा (एस.आर. हॉस्पिटल, दुर्ग), तकनीकी (वेदांता स्किल स्कूल) एवं बैंकिंग (नीट इंटरएक्ट फाइनेंस बैंकिंग) सहित विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। रोजगार मेला में 10वीं, 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती की जाएगी। जिसमें टेक्नीशियन के 150, सेल्स एग्जीक्यूटिव के 50, फिटर, वेल्डर, सोलर सिस्टम इंस्टॉलर, प्लंबर एवं टेक्नीशियन के 95, सुपरवाइजर के 75, सिक्योरिटी गार्ड के 620, कंप्यूटर ऑपरेटर के 40, डॉक्टर के 70, मेडिकल टेक्नीशियन के 35, नर्सिंग के 35, मैनेजर के 55, कुल 1,470 पदों पर भर्ती की जाएगी।

जिला रोजगार अधिकारी ने जिले के पात्र एवं इच्छुक युवाओं से अपील की है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर रोजगार मेले में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ लें।

नशे में मदहोश स्कूल पहुंचे खोरखोरीपारा के प्र.पाठक का वीडियो हुआ वायरल

जिस पर है बच्चो के भविष्य संवारने का जिम्मा, वही सवालों के घेरे

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर।प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर समय-समय पर सामने आने वाली घटनाएं इन प्रयासों पर सवाल खड़े कर रही हैं। जिले के ग्राम पंचायत साल्ही के प्राथमिक शाला खोरखोरीपारा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विद्यालय के प्रधानपाठक हरिनंदन सिंह कथित रूप से नशे की हालत में विद्यालय परिसर के बाहर लोटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना प्रेमनगर विधायक के गृह क्षेत्र के समीप की बताई जा रही है। यही वजह है कि यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि के गृह क्षेत्र के आसपास स्थित विद्यालय की स्थिति को लेकर ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं, तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक केवल पढ़ाई ही नहीं कराते, बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण और संस्कारों के भी प्रमुख आधार होते हैं। ऐसे में यदि किसी शिक्षक का आचरण विवादों में आता है तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों, अभिभावकों और पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर पड़ता है। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने शिक्षा विभाग से निष्पक्ष जांच व कड़ी विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई-बीईओ

इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी अवधेश साहू ने कहा कि मामला गंभीर है और उनके संज्ञान में आया है। पूरे प्रकरण की जांच कर उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-विधायक भूलन

इधर मामले को प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मराबी ने काफी गम्भीरता से लिया है। उन्होंने बीईओ से कार्रवाई के लिए कहा है। विधायक ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कृत्य किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जाएगा। स्कूल के शिक्षक द्वारा किये गए इस कृत्य से बच्चो पर विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और बच्चे अपना बेहतर भविष्य गढ़ सके इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।शिक्षक की जो हरकत सामने आई है वह काफी शर्मनाक है जो बर्दास्त नहीं होगी।

निलंबित किये गए नशेड़ी प्रधान पाठक

खोरखोरीपारा साल्ही के प्रधान पाठक हरिनन्दन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने संज्ञान में आने के बाद श्रीमती लता बेक, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त प्राप्त शिकायत की जांच अवधेश कुमार साहू बीईओ रामानुजनगर के द्वारा किया गया। प्रथम दृष्ट्या में शिकायत सही पाये जाने पर जांच प्रतिवेदन के आधार हरिनन्दन सिंह प्रधान पाठक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये तत्काल प्रभाव से निलबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है।

11 जुलाई को सियान सदन में होगी पेंशनर्स समाज की मासिक बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज, जिला सरगुजा ईकाई की मासिक बैठक शनिवार, 11 जुलाई को सायं 4 बजे से स्थानीय सियान सदन में आयोजित होगी। जिला ईकाई के सचिव त्रिलोचन यादव एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जे.पी. चौबे ने बताया कि बैठक में आगामी प्रांताध्यक्ष के चुनाव को लेकर 30 जून को रायपुर में हुई बैठक की जानकारी सदस्यों को दी जाएगी।

धारा-49 पर याचिका में मिली राहत

बैठक में धारा-49 के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। सरकार द्वारा सहमति के बहाने पेंशनर्स के जायज स्वत्वों के भुगतान में देरी के खिलाफ समाज ने याचिका दायर की थी, जिस पर सकारात्मक निर्णय प्राप्त हुआ है। इस फैसले की विस्तृत जानकारी सदस्यों को दी जाएगी।इसके अलावा पेंशनर्स की अन्य सामयिक समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। संगठन के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, सचिव त्रिलोचन यादव एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जे.पी. चौबे ने जिले के सभी सम्मानित पेंशनर्स से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं ने बदली जनेऊराम के परिवार की जिंदगी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं जरूरतमंद और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। भूमिहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल देने के लिए संचालित योजनाओं से हजारों परिवारों को नई दिशा मिली है।

विकासखंड के ग्राम करजी निवासी जनेऊराम नायक का परिवार शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर आज आत्मविश्वास के साथ

जीवनयापन कर रहा है। जनेऊराम ने बताया कि वे भूमिहीन परिवार से हैं और लंबे समय से कृषि मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते रहे हैं। सीमित आय में परिवार की जरूरतों को पूरा करना कठिन था, लेकिन शासन की योजनाओं से अब आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

10 हजार की वार्षिक सहायता बनी राहत

जनेऊराम को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा, ₹इस सहायता से घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की जरूरतों और दैनिक खर्चों में सहयोग मिलता है। पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परेशानी होती थी, अब आर्थिक बोझ कम हुआ है।

कच्चे से पक्का घर का सपना हुआ साकार

परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का आवास स्वीकृत होना रही। पहले कच्चे मकान में बरसात के दिनों में काफी कठिनाई होती थी।

सरेंडर के बाद 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रामगोपाल अग्रवाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रामगोपाल अग्रवाल को 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) की रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल ने 3 साल बाद बुधवार को ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया था।

9 दिन की कस्टोडियल रिमांड मिली

गुरुवार को मेडिकल जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने अग्रवाल को रायपुर कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 दिन यानी 17 जुलाई तक की कस्टोडियल रिमांड दी है। इस दौरान ईओडब्ल्यू उनसे घोटाले से जुड़े बिंदुओं पर पूछताछ करेगी।

राजीव भवन तक पैसा पहुंचाने का आरोप

ईओडब्ल्यू का दावा है कि कोयला लेवी घोटाले की जांच में सूर्यकांत तिवारी की जब्त डायरी में कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों रुपए की एंट्री मिली है। एजेंसी के मुताबिक यह रकम रामगोपाल अग्रवाल के जरिए राजीव भवन तक पहुंची थी। इसके अलावा शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर और उसके लोगों ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए। कस्टम मिलिंग केस में भी रोशन चंद्राकर ने करोड़ों रुपए रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाने का आरोप है।

बेटे वैभव से भी हुई पूछताछ

ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल के बेटे वैभव अग्रवाल से भी 2 दिन तक लंबी पूछताछ की है। उनसे रामगोपाल के पिछले 3 सालों के ठिकानों, आर्थिक लेन-देन और कथित नेटवर्क से जुड़े सवाल किए गए।

3 साल से थे गायब

रामगोपाल अग्रवाल करीब 3 साल से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे। इस दौरान उनके देश और विदेश में होने की चचाएं भी सामने आती रहीं।

शा.उ.मा.वि. में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव एवं निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह सम्पन्न

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारगवा में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव एवं निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत साइकिल वितरण समारोह सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज मुख्य अतिथि और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दिव्या सिंह सिसोदिया अध्यक्ष के रूप में शामिल हुईं।

मां सरस्वती की वंदना से हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्राचार्य संजीव कुमार सिंह ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर गत वर्ष के परीक्षा परिणाम और गतिविधियों की जानकारी दी।

7 साल की मेहनत से 50 साल सुखमय होंगे - दिव्या सिंह सिसोदिया

जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दिव्या सिंह सिसोदिया ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल का समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है।₹इस 7 साल में मेहनत करेंगे तो आपके आने वाले 50 साल सुखमय होंगे।₹ उन्होंने मोबाइल का सकारात्मक उपयोग करने की सलाह दी और कहा कि ₹मोबाइल रील देखने के लिए नहीं, रियल लाइफ चुनौतियों को हल करने का उपकरण है।₹

विधायक ने दिया लक्ष्य का मंत्र

मुख्य अतिथि विधायक प्रबोध मिंज ने कहा, ₹आप अपने जीवन का लक्ष्य प्रबल रखिए और उसी पर मेहनत करके सकारात्मक सोच रखिए। आप नौकरी करें या व्यवसाय, सफलता अवश्य मिलेगी।₹ उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के शिक्षित होने से पूरे परिवार और गांव का उत्थान होता है।

48 छात्राओं को मिली साइकिल, नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत

समारोह में नवप्रवेशी बच्चों को मिष्ठान खिलाकर पुस्तक एवं गणवेश प्रदान किए गए। निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत विद्यालय की 48 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई।

ई-केवाईसी संशोधन कार्य हेतु 152 सीएससी वीएलई किये गए प्रशिक्षित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर ।जिले में ई-केवाईसी से संबंधित संशोधन कार्यों को सुचारू, त्रुटिहीन एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के उद्देश्य से गुरुवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए 152 कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई शामिल हुए ।जिन्हें मुख्य प्रशिक्षक एन.डी. तिवारी ने ई-केवाईसी प्रक्रिया में होने वाले संशोधनों, तकनीकी पहलुओं तथा पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान की विस्तृत

जानकारी दी। उन्होंने फील्ड स्तर पर सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान के लिए भी आवश्यक सुझाव साझा किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रम विभाग के अधिकारी, सीएससी जिला प्रबंधक, जिले के सभी श्रम निरीक्षक तथा बड़ी संख्या में वीएलई उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी वीएलई को निर्देशित किया कि वे आम नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करते हुए ई-केवाईसी संशोधन कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण करें।

कोल्हुआ शिविर में 396 ग्रामीणों हुआ उपचार, वितरित किये गए 150 मच्छरदानी व 101वस्त्र

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिहारपुर। श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा मकरी कुटिया के तत्वावधान तथा स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के सहयोग से दूरस्थ एवं सुविधाविहीन क्षेत्र ग्राम कोल्हुआ में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुँचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. सुरेश मिश्रा, डॉ. अमन भगत, डॉ. उपेंद्र सिंह, डॉ. प्रभात रंजन उपाध्याय, डॉ. विकास दुबे, डॉ. चंद्रकला मिंज एवं समस्त स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग की टीम ने 396 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया। इनमें एलोपैथिक चिकित्सा से 200, होम्योपैथिक चिकित्सा से 127 तथा आयुर्वेद चिकित्सा से 69 मरीज लाभान्वित

हुए। सभी मरीजों को आवश्यक परामर्श एवं निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान सेवा कार्य के तहत मलेरिया से बचाव हेतु 150 मच्छरदानी तथा 101 बच्चो को वस्त्र प्रदान किए गए। यह सेवा अभियान परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम जी एवं पूज्य बाबा गुरुपद संभव राम की कृपा एवं गुरु प्रेरणा से संपन्न हुआ। श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा केतार से डॉ. बी. एन. पांडेय ने सहभागिता निभाई। मां गढ़वतिया देवी धाम, महुली के सेवक तुलसी जायसवाल, बृजेश देवांगन, शिशुपाल जायसवाल, रामलाल पंडों, बसंतलाल साहू, शिवकुमार जायसवाल, सियाराम साहू, अमरजीत सिंह, रंजीत सिंह एवं बेहर देवांगन जी ने सेवा कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। आयोजन में श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा मकरी कुटिया आश्रम, गढ़वा झारखंड के बिहारीराम बाबा, पूनमचंद गोयल, दिनालाल सिन्हा, जशवंत गुप्ता, साधु, अनुपलाल यादव, मुकेश गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, विकास गुप्ता, रमेश यादव, मनोज पासवान एवं अभय यादव का विशेष योगदान रहा।

स्कूली शिक्षा में 2027 से बड़ा बदलाव, पहली में एडमिशन 6 साल में, 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल अनिवार्य होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

2027 से बदलेगा शिक्षा सत्र-1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल

2027 से शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। स्कूल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से खुलेंगे। अप्रैल में ही प्रवेश

प्रक्रिया पूरी कर स्टूडेंट्स को पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरित की जाएंगी। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। यह व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू होगी।

क्यों लिया गया फैसला?

फिलहाल स्कूल 16 जून से खुलते हैं। स्कूल खुलने के बाद कई दिनों तक प्रवेश, किताबें, यूनिफॉर्म, साइकिल बांटने में समय लगता है, जिससे नियमित पढ़ाई जुलाई तक शुरू हो पाती है। विभाग का कहना है कि नए बदलाव से पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा, समय पर सिलेबस पूरा होगा और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सुधार आएगा।

सीबीएसई और सीजी बोर्ड का अंतर होगा खत्म

स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक सीबीएसई स्कूल अप्रैल से पढ़ाई शुरू करते हैं, जबकि सीजी बोर्ड स्कूल जून के मध्य में खुलते हैं। ढाई महीने के अंतर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और पाठ्यक्रम पूरा करने में दिक्कत होती थी। अब दोनों व्यवस्थाओं के बीच यह अंतर खत्म हो जाएगा।

3 महीने की छूट का प्रावधान

अगर कोई बच्चा 1 अप्रैल तक 6 साल का नहीं है, लेकिन 1 जुलाई तक उम्र पूरी हो जाती है, तो उसे अधिकतम 3 महीने की छूट देकर प्रवेश दिया जा सकेगा।

किन पर लागू नहीं होगा नियम?

जो बच्चे मान्यता प्राप्त स्कूल की प्री-प्राइमरी (केजी) पास करके पहली कक्षा में जा रहे हैं, उन पर नई उम्र सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे छात्रों को टीसी, अंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश मिलेगा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर भी यही नियम लागू होगा।

गुणवत्ता सुधारना लक्ष्य-शिक्षा सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कहा कि बदलाव का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। अभी पुस्तकों के वितरण का लक्ष्य जून तक रहता है, लेकिन कई बार जुलाई तक पहुंच जाता है।

सम्पादकीय

ट्रंप का फीफा पर दबाव बनाना असामान्य कदम

पिछले करीब डेढ़ साल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में टैरिफ, अर्थव्यवस्था, व्यापार, शांति, भू-राजनीति, सैन्य हस्तक्षेप और रणनीतिक दबाव से उथल-पुथल मचा रखी है। हाल का मामला इन सबसे अलग है। अब ट्रंप ने खेल के मैदान में भी एंट्री मारकर दुनियाभर के खेल संघों को चौंका दिया है। उन्होंने फीफा पर दबाव डालकर अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन पर लगा एक मैच का प्रतिबंध (निलंबन) रद्द करवा दिया। इसके लिए ट्रंप ने फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो से व्यक्तिगत रूप से बात की। हालांकि अमेरिकी टीम को बेल्जियम ने 3-1 से करारी मात दी और वह क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई तक नहीं कर पाई। देखा जाए तो यह प्रकरण अपने आप में एक अजूबा है। सामान्यतः किसी भी देश के खिलाड़ी के लिए मैच में रेफरी का फैसला आने के बाद उसे चुनौती दी जाती है और फिर फीफा का निर्णायक मंडल पूरे मामले की समीक्षा कर अपना निर्णय देता है। स्थापित प्रक्रिया का यही उद्देश्य होता है कि खेल के नियम सभी टीमों और खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू हों तथा किसी भी तरह के राजनीतिक या बाहरी दबाव का प्रभाव निर्णयों पर न पड़े। यदि किसी शक्तिशाली देश का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सीधे हस्तक्षेप कर फैसले बदलवाने लगे तो खेलों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। ऐसा पहली बार है जब किसी देश के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप कर अपने खिलाड़ी का निलंबन हटवाया है। फीफा ने भले ही इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताने का प्रयास किया हो, लेकिन दुनिया भर के खेल विशेषज्ञों और खेल संघों के बीच इस घटनाक्रम को लेकर असहजता दिखाई दी है। फीफा लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि वह राजनीति से स्वतंत्र संस्था है। कई देशों के फुटबॉल महासंघों पर सरकारी हस्तक्षेप के आरोप में प्रतिबंध तक लगाए जा चुके हैं। ऐसे में यदि किसी महाशक्ति के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप को अलग नजरिए से देखा जाता है तो दोहरे मानदंडों की बहस तेज होना स्वाभाविक है। मैदान पर खिलाड़ी की पहचान उसके प्रदर्शन से होती है, न कि उसके देश की राजनीतिक ताकत से। यदि किसी खिलाड़ी को यह संदेश मिले कि राजनीतिक प्रभाव से खेल संबंधी फैसले बदले जा सकते हैं, तो इससे खेल भावना को आघात पहुंचेगा। हालांकि घटनाक्रम का खेल परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका बेल्जियम से हार गया और बालोगुन का मैदान पर उतरना भी टीम को आगे नहीं ले जा सका। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी खेल में अंतिम फैसला खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही करता है, न कि राजनीतिक दबाव। जीत और हार खेल का स्वाभाविक हिस्सा हैं और इन्हें स्वीकार करना ही खेल भावना की असली पहचान है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब आने वाले वर्षों में अमेरिका कई बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है। विशेष रूप से लॉस एंजिल्स ओलंपिक को लेकर दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं। ऐसे में यदि राजनीतिक हस्तक्षेप की धारणा मजबूत होती है तो अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं की निष्पक्षता और मेजबान देश की भूमिका दोनों पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि सरकारें खेलों के विकास, खिलाड़ियों की सुविधाओं और खेल ढांचे को मजबूत करने तक अपनी भूमिका सीमित रखें तथा मैदान के फैसले खेल संस्थाओं और नियमों पर ही छोड़ दें। खेल तभी खेल बने रहेंगे, जब उन पर राजनीति की छाया हावी न हो।

मुद्दा
ममता कुशवाहा

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस साल का फीफा विश्व कप अब तक का सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला विश्व कप बन सकता है। यह चेतावनी केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक खेल आयोजनों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है। कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप है, कहीं बाढ़ और चक्रवात तबाही मचा रहे हैं, तो कहीं जंगलों में आग लाखों हेक्टेयर भूमि को निगल रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो पृथ्वी का भविष्य और अधिक संकटग्रस्त हो जाएगा।

खेल महाकुंभ की पर्यावरणीय चुनौती

फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, सपनों और उत्साह का प्रतीक है। विश्व कप जैसे आयोजनों के दौरान पूरा विश्व एक साझा उत्सव में डूब जाता है, लेकिन खेलों की चमक-दमक और उत्साह के पीछे एक ऐसा पक्ष भी छिपा है, जिस पर लंबे समय तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यह पक्ष है पर्यावरण पर पड़ने वाला उसका प्रभाव। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस साल का फीफा विश्व कप अब तक का सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला विश्व कप बन सकता है। यह चेतावनी केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक खेल आयोजनों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है। कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप है, कहीं बाढ़ और चक्रवात तबाही मचा रहे हैं, तो कहीं जंगलों में आग लाखों हेक्टेयर भूमि को निगल रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो पृथ्वी का भविष्य और अधिक संकटग्रस्त हो जाएगा।

ऐसे समय में जब प्रत्येक क्षेत्र से पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जा रही है, तब खेल जगत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। खेलों के विशाल आयोजन, जिनमें लाखों दर्शक और हजारों खिलाड़ी शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में चल रहा है। यह पहली बार होगा जब विश्व कप में 48 टीमें भाग लेंगी। पहले की तुलना में अधिक टीमें, अधिक मैच और अधिक शहर इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। कुल 16 शहरों में 104 मैच खेले जाएंगे। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, अधिकारियों, पत्रकारों और दर्शकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करनी होगी। यही वह प्रमुख कारण है जिसके चलते कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि की आशंका व्यक्त की जा रही है। कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत हवाई यात्रा होती है। विश्व कप जैसे आयोजनों में लाखों लोग विमानों के माध्यम से हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जब टीमें एक देश से दूसरे देश और एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, तब ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ता है। वर्ष 2026 के इस विश्व कप में तीन देशों के अनेक शहरों को मेजबानी दी गई है। इससे यात्राओं की दूरी और संख्या दोनों में वृद्धि होगी। यही कारण है कि शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आयोजन पर्यावरणीय दृष्टि से अब तक का सबसे भारी विश्व कप साबित हो सकता है। दरअसल, खेल आयोजनों का पर्यावरणीय प्रभाव केवल यात्रा तक सीमित नहीं होता। स्टेडियमों के निर्माण और रखरखाव में भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। विशाल स्टेडियमों को रोशन करने, वातानुकूलित रखने, सुरक्षा व्यवस्था संचालित करने और प्रसारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारी बिजली की आवश्यकता होती है। यदि यह ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त हो रही है, तो उसका सीधा संबंध कार्बन उत्सर्जन से जुड़ जाता है। आज खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है। यह एक

विशाल वैश्विक उद्योग बन चुका है। अरबों डॉलर के निवेश, प्रायोजन और व्यावसायिक हित इसके साथ जुड़े हुए हैं। फुटबॉल क्लब, प्रसारण कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां खेल आयोजनों को एक बड़े आर्थिक अवसर के रूप में देखती हैं। जब आर्थिक लाभ पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर हावी होने लगता है, तब समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। यही चिंता शोधकर्ताओं ने भी व्यक्त की है कि फुटबॉल का बढ़ता व्यावसायीकरण और आयोजनों का निरंतर विस्तार पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। आज कल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खेलों पर भी पड़ रहा है। बढ़ता तापमान खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है। कई देशों में अत्यधिक गर्मी के कारण मैचों का समय बदलना पड़ा है। कुछ स्थानों पर मौसम की अनिश्चितता के कारण प्रतियोगिताओं को स्थगित करना पड़ा। वर्षा, तूफान और गर्म हवाएं खेल आयोजनों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। अर्थात जिस जलवायु संकट को खेल उद्योग अनजाने में बढ़ा रहा है, वही संकट अब खेलों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। वैज्ञानिक आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बना देते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति से पहले यह स्तर लगभग 280 पीपीएम था, जबकि आज यह 430 पीपीएम से अधिक पहुंच चुका है। यह वृद्धि केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि पृथ्वी के बदलते पर्यावरण का संकेत है। बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र को अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने की आवश्यकता है। फुटबॉल और अन्य खेल संगठनों ने हाल के वर्षों में पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं की घोषणाएं अवश्य की हैं। कई संगठनों ने कार्बन न्यूट्रल बनने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने की योजनाएं प्रस्तुत की हैं। कुछ स्टेडियम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। यदि आयोजन लगातार बड़े और अधिक विस्तृत होते जाएंगे, तो पर्यावरणीय लाभ सीमित रह जाएंगे। इस तरह भविष्य के खेल आयोजनों के लिए एक नई सोच की आवश्यकता है। आयोजकों को ऐसे मॉडल अपनाने होंगे जिनमें यात्रा की दूरी कम हो, स्थानीय संसाधनों का अधिक उपयोग हो और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाए। दर्शकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टेडियमों के निर्माण में पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का प्रयोग बढ़ाना होगा। साथ ही आयोजनों के आकार और विस्तार को लेकर भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि खेल जगत अपनी लोकप्रियता का उपयोग पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए करे। फुटबॉल खिलाड़ियों और खेल सितारों का प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ता है। यदि वे जलवायु संरक्षण का संदेश देंगे, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन भी बन सकता है। फीफा विश्व कप 2026 को लेकर उठी कार्बन उत्सर्जन की चिंता हमें एक व्यापक सच्चाई की ओर संकेत करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि खेलों की चमक के साथ पर्यावरणीय चेतना का प्रकाश भी उतना ही प्रखर हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ, संतुलित और सुरक्षित पृथ्वी पर अपने सपनों का खेल खेल सकें।

(लेखिका शिक्षिका हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंथन
सोनम लववंशी

मां की गोद से डे-केयर तक ... क्या सुरक्षित है बचपन

किसी भी समाज का भविष्य उसके संसद भवनों, शेयर बाज़ारों या कॉर्पोरेट टावरों में नहीं, उन नन्हें हाथों में पलता है जो अभी दुनिया पर भरोसा करना सीख रहे हैं। यही कारण है कि किसी राष्ट्र की सभ्यता का सबसे बड़ा पैमाना यह नहीं होता कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, बल्कि यह होता है कि उसके सबसे मासूम नागरिक कितने सुरक्षित हैं। जब दो-तीन वर्ष का एक बच्चा, जो बोलकर अपना दर्द भी बता नहीं सकता, उसी स्थान पर प्रताड़ित होने लगे जहां उसे सुरक्षा और स्नेह मिलना चाहिए, तब ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रहती, पूरे समाज के नैतिक ढांचे पर प्रश्नचिह्न बन जाती है। बेंगलुरु के एक कॉर्पोरेट परिसर स्थित डे-केयर सेंटर से सामने आए कथित दुर्व्यवहार के वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वीडियो में छोटे बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। बाल अधिकार संस्थाओं ने हस्तक्षेप किया और संबंधित डे-केयर केंद्र को बंद करना पड़ा। यह कार्रवाई आवश्यक थी, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि यदि यह वीडियो सामने नहीं आता, तो क्या उन बच्चों की पीड़ा कभी व्यवस्था तक पहुंच पाती? क्या हमारे संस्थागत तंत्र की संवेदनशीलता अब केवल वायरल वीडियो पर निर्भर हो गई है? भारत तेज़ी से बदल रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, महानगर फैल रहे हैं और लाखों महिलाएं कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में डे-केयर अब सुविधा नहीं, सामाजिक आवश्यकता बन चुका है। सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की बात करती है।

कॉर्पोरेट जगत 'समावेशी कार्यस्थल' और 'वर्क-लाइफ बैलेंस' के दावे करता है। इस पूरे विमर्श में सबसे अहम सवाल अक्सर छूट जाता है कि जब माता-पिता कार्यस्थल पर होंगे, तब उनके छोटे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा का प्रावधान किया गया। दूसरी ओर केंद्र सरकार पालना योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी-सह-क्रेच व्यवस्था का विस्तार कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में 14,599 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2,448 क्रेच संचालित हैं। उद्देश्य स्पष्ट है कामकाजी महिलाओं को सहयोग और छोटे बच्चों को सुरक्षित देखभाल उपलब्ध कराना। लेकिन यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। यदि योजनाएं हैं, कानून हैं और संस्थाएँ भी हैं, तो फिर अभिभावकों का भरोसा बार-बार क्यों टूट रहा है? इसका उत्तर केवल किसी एक कर्मचारी की क्रूरता में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की कमजोरी में छिपा है जहां डे-केयर खोलना अपेक्षाकृत आसान है, पर उसकी गुणवत्ता, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, पुलिस सत्यापन और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था अब भी बिखरी हुई है। बच्चों की सुरक्षा केवल भवन, खिलौनों और रंगीन दीवारों से सुनिश्चित नहीं होती; वह प्रशिक्षित और संवेदनशील मानव संसाधन से सुनिश्चित होती है। यूनिसेफ और प्रारंभिक बाल विकास से जुड़े वैश्विक अध्ययन बताते हैं कि जीवन के पहले पांच वर्ष बच्चे के मस्तिष्क और व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे निर्णायक होते हैं। इसी दौर में मिला प्रेम, सम्मान और सुरक्षा उसके पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं।

इसके विपरीत भय, अपमान और हिंसा उसके भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसलिए डे-केयर केवल बच्चों को कुछ घंटों तक रखने की जगह नहीं होता यह भविष्य गढ़ने का स्थान है। यदि वही स्थान भय का पर्याय बन जाए, तो उसका नुकसान केवल एक परिवार नहीं, पूरा समाज उठाता है। बेंगलुरु की घटना को किसी एक शहर या एक कंपनी की समस्या मानकर भुला देना आसान होगा। कठिन काम यह स्वीकार करना है कि यह घटना हमारी नीतियों, हमारी निगरानी व्यवस्था और हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं की कमियों को उजागर करती है। अंततः किसी भी राष्ट्र का भविष्य संसद की बहसों, आर्थिक सर्वेक्षणों या कॉर्पोरेट मुनाफ़ों में नहीं लिखा जाता। वह उन नन्हे कदमों में आकार लेता है जो अभी दुनिया पर भरोसा करना सीख रहे हैं। यदि हम उस भरोसे की रक्षा नहीं कर सके, तो इतिहास हमारी आर्थिक उपलब्धियों से अधिक हमारी नैतिक विफलताओं को याद रखेगा। क्योंकि किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी परीक्षा उसके बच्चों की मुस्कान होती है। यदि वही मुस्कान भय में बदल जाए, तो विकास की सबसे चमकदार इमारतें भी भीतर से खोखली साबित होती हैं।

(लेखिका शोधार्थी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

राम सब घट मेरा साइयां

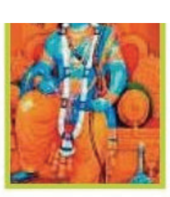

संकलित
दर्शन

पूरे संसार में राम का निवास है, सबमें भगवान हैं और हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है। कबीर ने कहा है-'राम सब घट मेरा साइयां'... राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में हैं। सदा सर्वदा सबके हृदय में रहेंगे, लेकिन हमारे स्वार्थ, हमारे हेतु, हमारी मानसिकताओं के कारण कभी-कभी हम राम को साधन बना बैठते हैं। इसलिए हम राम को सही रूप में नहीं समझ पाते। प्रत्येक व्यक्ति में यदि हमें सिया राम के दर्शन होने लगें तो तमाम भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। जातीय आधार पर भेदभाव काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए धर्माचार्यों को आगे आना होगा। धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या फिर सामाजिक क्षेत्र, अंतिम व्यक्ति पूज्य होना चाहिए। अगर अंतिम व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तक पहुंचें। भारतीय दर्शन में इहलोक और परलोक की बात आती है। इहलोक और परलोक का कल्याण करने की बात मेरी दृष्टि में इह यानी अपने संसार के साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास करना ही इहलोक और परलोक को सुधारना है। दूसरों के कल्याण की भावना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम व्यापक व विराट की संतान हैं, इसलिए दूसरों के कल्याण का भारतीय सोच पूरे विश्व के कल्याण का सोच है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो दुनिया के सभी देशों के कल्याण की बात करते हैं।

मानवता संस्कारों से पनपती है

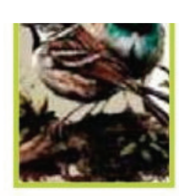

संकलित
प्रेरणा

टी.एन. शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मसूरी जा रहे थे। परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से निकलते हुऐ रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों पर गौरैया के कई सुन्दर घोंसले बने हुए हैं। यह देखते ही उनकी पत्नी ने अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए गौरैया के दो घोंसले लेने की इच्छा व्यक्त की तो उनके साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक छोटे से लड़के को बुलाया, जो वहां मवेशियों को चरा रहा था। उसे पेड़ों से तोड़ कर दो गौरैया के घोंसले लाने के लिए कहा। लड़के ने इनकार में सर हिला दिया। शेषन ने इसके लिए लड़के को 10 रुपए देने की पेशकश की। फिर भी लड़के के इनकार करने पर शेषन ने बढ़ा कर 50 रुपए देने की पेशकश की। फिर भी लड़के ने हामी नहीं भरी। पुलिस ने तब लड़के को धमकी दी और उसे बताया कि साहब जज हैं और तुझे जेल में भी डलवा सकते हैं। गंभीर परिणाम भुगतने पढ़ेंगे। लड़का तब श्रीमती और शेषन के पास गया और कहा- साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन घोंसलों में गौरैया के छोटे बच्चे हैं अगर मैं आपको दो घोंसले दूं, तो जो गौरैया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गई हुई है, जब वह वापस आएगी और बच्चों को नहीं देखेगी तो बहुत दुःखी होगी जिसका पाप मैं नहीं ले सकता। यह सुनकर टी.एन. शेषन दंग रह गए। शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है- मेरी स्थिति, शक्ति और आईएएस की डिग्री सिर्फ उस छोटे, अनपढ़, मवेशी चराने वाले लड़के द्वारा बोले गए शब्दों के सामने पिघल गई।

सटाका

आज की पाती

डिजिटल तकनीक का करें सही उपयोग

आज बच्चों के सामने सबसे बड़ा खतरा केवल इंटरनेट का बढ़ता उपयोग नहीं, बल्कि उसका अनियंत्रित और असुरक्षित उपयोग है। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा, ज्ञान और संवाद के नए द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ ही बच्चों का बचपन साइबर खतरों की गिरफ्त में आता जा रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर बीतने वाला बढ़ता समय उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। डिजिटल युग से बच्चों को दूर रखना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरकार, तकनीकी कंपनियां, विद्यालय, अभिभावक और समाज यदि मिलकर प्रयास करें, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां बच्चे इंटरनेट के उपभोक्ता नहीं, बल्कि सुरक्षित, जागरूक, सम्मानित और सशक्त नागरिक बनकर देश के भविष्य को नई दिशा दें।

- मनोज शर्मा, करनाल

ट्रेंड

सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना गर्व की बात है। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरी दोस्ती और दुनिया में भारत के बढ़ते सम्मान का एक और प्रमाण है।
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय बाल विकास मंत्री

जनता को विकल्प दें

मोदी जी कृपया जनता को विकल्प दें। देश के हर पेट्रोल पंप पर ई10, ई20 और ई0 उपलब्ध होने चाहिए। यह फैसला जनता का होना चाहिए कि वे अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलवाना चाहते हैं, सरकार का नहीं।
-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

जवाबदेही तय नहीं

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा देशभर के गांवों तक पहुंच गया है और इसे लेकर सभी लोगों में व्यापक आक्रोश है। भाजपा-आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मिलकर एकतरफा तरीके से मंदिर ट्रस्ट का गठन किया, लेकिन किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की गई।
- अशोक गहलौत, पूर्व सीएम, राजस्थान

तेल कंपनियों को लाभ

दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम गिरने से पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी कमी आई है और दूसरे देशों की जनता को तेल के घटे दामों के रूप में लाभ मिला है लेकिन इसके विपरीत भारत में भाजपा सरकार दाम नहीं घटा रही है और सरकार कंपनियों को लगातार फायदा पहुंचाने में लगी है।
- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

करंट अफेयर

ईंधन भंडार घटने से पूरे क्यूबा में बिजली आपूर्ति हुई ठप

ईंधन भंडार में लगातार कमी और जर्जर होती बिजली वितरण व्यवस्था के बीच सोमवार को पूरे क्यूबा में बिजली गुल हो गई। करीब एक करोड़ की आबादी वाले इस द्वीपीय देश में बिजली अपूर्ति ठप होने की जानकारी सरकारी बिजली कंपनी 'इलेक्ट्रिक यूनियन' ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर दी। कंपनी ने कहा कि बिजली बाधित होने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं, ऊर्जा एवं खनन मंत्रालय ने बताया कि बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

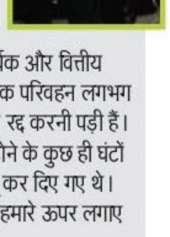

क्यूबा में इस वर्ष जनवरी से ही ईंधन का गंभीर संकट बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्यूबा को तेल बेचने वाले या उसकी आपूर्ति करने वाले देशों पर शुल्क लगाने की चेतावनी दिए जाने के बाद से देश का आर्थिक और वित्तीय संकट और गहरा गया है। ईंधन संकट के कारण सार्वजनिक परिवहन लगभग ठप हो गया है, वहीं अस्पतालों में हजारों निर्धारित सर्जरी भी रद्द करनी पड़ी हैं। ऊर्जा मंत्री विसेंटे दे ला ओ लेवी ने बताया कि बिजली गुल होने के कुछ ही घंटों बाद देशभर में छोटे-छोटे विद्युत तंत्र (माइक्रोसिस्टम) चालू कर दिए गए थे। उन्होंने कहा, 'हम जटिल स्थिति का सामना कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों के कारण और गंभीर हो गई है।

ऑफ बीट

आधा अरब क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे

क्षुद्रग्रह हमारे सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे चट्टानों के टुकड़े हैं। चार मीटर से अधिक व्यास वाले लगभग आधा अरब क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, जो हमारे सौर मंडल से लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजरते हैं – लगभग पृथ्वी के समान गति से। ज्यादातर मामलों में, सबसे छोटे क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर काफी हद तक टूट जाते हैं, और सतह तक भी नहीं आ पाते हैं। जब एक छोटा क्षुद्रग्रह (या उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह से छोटी वस्तु) पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है, तो यह एक चमकीला 'आग का गोला' बन जाता है – एक शूटिंग स्टार या उल्का का एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला और उजला संस्करण। यदि वस्तु का कोई बचा हुआ टुकड़ा जमीन से टकराता है, तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है। अधिकांश वस्तु वायुमंडल में जल जाती है। प्रति वर्ष एक बार, औसतन, चार मीटर का क्षुद्रग्रह पृथ्वी की सतह से टकराता है। यदि आपने उस सतह क्षेत्र को दोगुना कर दिया, तो आपको प्रति वर्ष दो मिलेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या 6,400 किमी है। दोगुने सतह क्षेत्रफल वाले एक गोले की त्रिज्या 9,000 किमी है। तो, प्रति वर्ष लगभग एक बार, चार मीटर का क्षुद्रग्रह पृथ्वी की सतह के 2,600 किमी के भीतर आएगा – 9,000 किमी और 6,400 किमी के बीच का अंतर।

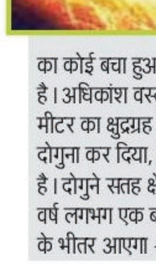

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र० /ब-121/2025-26.

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रामरति उर्फ भुन्दो आ० स्व० टिरकु, व अन्य 01, निवासी ग्राम सकालो, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अंतर्गत आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा०) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि ग्राम सकालो स्थित भूमि पुराना खसरा नंबर 1/32 नवीन खसरा नंबर 180 रकबा 0.500 हे० भूमि नवीन बंदोबस्त के दौरान त्रुटिवश अनावेदक क्र0 01 करमू आ० धनवार के नाम पर दर्ज हो गया है। जबकि उक्त भूमि पर आवेदिकागण काबिज काश्त हैं। आवेदिकागण द्वारा बंदोबस्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 24/07/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 08/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका अंकुर वर्मा आ०/ पति स्व० सुनील वर्मा व 04 अन्य जाति, निवासी गोपाल होटल के पीछे सत्तीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-सत्तीपारा, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 580, 581 रकबा 0.02, 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 23/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: https: // eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये लाख में)
1	194579 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला कबीरधाम वि.ख. पण्डरिया के भरतपुर से घोघरा मार्ग लंबाई 3.50 कि.मी. का पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य। सी.सी.मार्ग।	357.82
2	194650 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला राजनांदगांव (वर्तमान जिला –खैरागढ–छुईखदान–गण्डई) के राजनांदगांव कवर्धा पोडी मार्ग के कि.मी. 55/10 (राज्य मार्ग क्रं. – 05) पर घिरघोरी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	431.32
3	194659 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला कांकेर के संबलपुर–सिलपट मार्ग के कि.मी. 1/2 संबलपुर नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	384.23
4	194666 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला रायगढ के छुंईयापाली से भुईयापाली के मध्य कुरू नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	615.24
5	194668 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला रायगढ के रायगढ शहर केवडाबाडी बस स्टैंड से इंदिरा नगर मार्ग के मध्य लोकल नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	755.46
6	194669 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	रायगढ मेडिकल कॉलेज पहुंच मार्ग में बालसमुन्द नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	757.47
7	194674 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला रायपुर के उरला पठारीडीह–बेरला मार्ग पर (एम.डी.आर. नं. 396) में खारून नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1548.78
8	194675 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर के बेलबहरा से लालपुर मार्ग पर सुखाड बुधरा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	499.73
9	194677 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला जांजगीर चांपा के पुराना एन.एच. पर हसदेव नदी में जर्जर गेमन में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1301.72
10	194678 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला बिलासपुर के सरसेनी–सागर मार्ग में घोंघा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	219.89
11	194679 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला कोरबा के कोरबा रानीरोड सर्वमंगला मंदिर के मध्य हरादेव नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1325.23
12	194671 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला रायगढ के बनोरा से डुमरपाली मार्ग में सपनई नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	381.86
13	194672 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला रायगढ के चांदनी चौक से राजमहल के मध्य लोकल नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	399.83
14	194673 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला बस्तर के सिवनी से राजपुर मार्ग के कि.मी. 2/6 नारंगी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1560.38
15	194682 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर के पाराडोल से तेन्दुडांड मार्ग में हसदेव नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	896.43
16	194687 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला मुंगेली के घुण्डुकापा – पचोटिया मार्ग में रहन नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	331.20
17	194483 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	सकरबोगा से महापल्ली मार्ग में बडा रेलिंगवाल पुल निर्माण कार्य।	244.29
18	194698 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	गोपालपुर से भिखारीमाल (आंगनबाडी तक) मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. का निर्माण कार्य।	268.47

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथी सं.क.17 से सं.क्र. 18 दिनांक 24.07.2026 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 23.07.2026 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

मुख्य अभियंता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

जी 262701980/2

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की भारतीय भूमि पर कब्जा; केंद्र सरकार चूप क्यू

मुंबई : वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ड. प्रकाश आंबेडकर ने अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग क्षेत्र में चीन द्वारा भारतीय सीमा में अतिक्रमण के मुद्दे पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह जानकारी सही है तो यह केवल सीमा सुरक्षा का नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत गंभीर विषय है। केंद्र सरकार को इस मामले पर तत्काल देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ड. आंबेडकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग क्षेत्र की एक स्थानीय संस्था नाह वेलफेयर सोसाइटी ने 26 जून 2026 को सुबनसिरी जिले के उपायुक्त को एक पत्र लिखकर कहा है कि वर्ष 2020 तक जिन क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की आवाजाही होती थी, उन इलाकों पर अब चीन ने कब्जा कर लिया है। संस्था ने अपने पत्र में उन स्थानों का भी उल्लेख किया है, जहां से चीनी घुसपैठ हुई है और जहां अब भारतीय नागरिकों का प्रवेश संभव नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को होने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस चुप्पी से अनेक गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ड. प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर देश की सीमाओं की सुरक्षा और ₹लाल आंख दिखाने₹ की बात करते हैं तथा अपनी सरकार को मजबूत नेतृत्व वाली सरकार बताते हैं। लेकिन यदि वास्तव में चीन भारतीय भूमि पर कब्जा कर रहा है, तो केंद्र सरकार इस विषय पर मौन क्यों है आखिर सरकार इस पर कब कार्रवाई करेगी उन्होंने आगे कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश के दो क्षेत्रों में सैन्य बंकर बनाए हैं तथा सैन्य सामग्री के आवागमन के लिए दो हेलिपैड भी निर्मित किए हैं। यह जानकारी भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत गंभीर चुनौती है और इस पर तत्काल राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। ड. आंबेडकर ने भाजपा नेतृत्व तथा केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू से भी इस विषय पर स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी देने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि सीमा पर वास्तविक स्थिति क्या है और सरकार भारतीय भूमि की रक्षा के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठा रही है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल करते हुए कहा कि यदि चीन ने भारतीय सीमा के भीतर अतिक्रमण किया है, तो न तो सरकार की कथित ₹लाल आंख₹ दिखाई दे रही है और न ही ₹56 इंच के सीने₹ वाली सरकार की ओर से कोई निर्णायक कार्रवाई नजर आ रही है। ड. प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र सरकार से मांग की कि अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग क्षेत्र में चीन की गतिविधियों और सीमा की वास्तविक स्थिति पर तत्काल आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा भारतीय सीमा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होने विपक्ष नेता राहुल गांधी से कहा है की संसद के मान्सून सत्र मैं इस पर सरकार को घेरा जाये और सरकार पर इससे जबाब लिया जाये।

एनसीईआरटी किताब में बदलाव

देश के बंटवारे के साथ कांग्रेस की भूमिका, आंदोलन को फिर लिखा

8वीं की बुक 2026-27 के सत्र से पढ़ाई जाएगी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

एनसीईआरटी ने 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब जारी कर दी है. इस बार इतिहास के कई हिस्सों में बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर भारत के बंटवारे, कांग्रेस की भूमिका, वीडी सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े चैप्टर को नए तरीके से लिखा गया है। यह किताब अब 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई जाएगी। नई किताब में आजादी की लड़ाई से जुड़े कई हिस्सों को पहले के मुकाबले अलग तरीके से लिखा गया है। कुछ पुरानी बातें हटाई गई हैं तो कुछ नई जानकारी भी जोड़ी गई है।

तब बंटवारे पर अलग अलग राय थी

नई किताब में कहा गया है कि भारत का बंटवारा सिर्फ दो समुदायों के बीच मतभेद की वजह से नहीं हुआ। इसमें यह भी लिखा गया है कि कांग्रेस ने भी बड़े स्तर पर बंटवारे का विरोध किया था और उस समय पूरे देश में इस फैसले पर एक जैसी राय नहीं थी। साथ ही यह भी बताया गया है कि बंटवारे को स्वीकार करना सही फैसला था या नहीं, इस पर आज भी अलग-अलग राय है।

कांग्रेस के 'बेबसी' वाले हिस्से को हटाया

पहले वाली किताब में लिखा था कि बंटवारे के समय हुई हिंसा के दौरान कांग्रेस के नेता खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। नई किताब से इस हिस्से को हटा दिया गया है। हालांकि महात्मा गांधी के हिंसा पर दुख जताने वाले विचार अभी भी किताब में रखे गए हैं।

नेताजी वाले चैप्टर को भी बदला

बोस से जुड़े हिस्से में भी बदलाव किया गया है। पहले किताब में एडोल्फ हिटलर और नाजी विचारधारा का जिक्र था। नई किताब में इनका नाम हटा दिया गया है। अब सिर्फ इतना लिखा गया है कि नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के विरोधी देशों से मदद लेने की कोशिश की थी।

'भारत छोड़ो' में लोहिया, जयप्रकाश का नाम जुड़ा

भारत छोड़ो आंदोलन वाले चैप्टर में भी बदलाव किया गया है। पहले गांधी, नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं के नाम लिखे गए थे। अब इसकी जगह लिखा गया है कि कांग्रेस का लगभग पूरा नेतृत्व गिरफ्तार कर लिया गया था, साथ ही राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी विस्तार से बताया गया है।

क्रांतिदूत साहित्यकार मधुराज मधु के व्यक्तित्व और साहित्यिक उपलब्धियों पर चर्चा समारोह

मुंबई ; वरिष्ठ क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार ,फिल्म गीतकार मधुराज मधु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मधुमास साहित्यिक मंच के तत्वावधान में उनके व्यक्तित्व और साहित्यिक उपलब्धियां पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया .कांदिवली में उषा मधु, चंदन मधु द्वारा आयोजित चर्चा सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ लेखक साहित्यकार डॉ महेंद्र ने की. सभी वक्ताओं ने सर्वहारा समाज के उत्थान के लिए समर्पित मधुराज मधु के साहित्य की न केवल प्रशंसा की बल्कि उनका अनुसरण करने का आह्वान भी किया. ज्ञातव्य हो कि उनके उपन्यासों पर जहां फिल्में भी बन चुकी हैं वही कई फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

कई राज्यों में दिखा खजाने का 'खेल' तो कहीं नहीं बैठ पा रहा राजनीतिक तालमेल

रिटायर अफसर के घर मिला 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी

एजेंसी ▶▶ लखनऊ

उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग से रिटायर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ललित कुमार कुबेर निकला। उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग ने 7- 8जुलाई को छापा मारा तो 'कुबेर का खजाना' मिला। इतना सोना चांदी, जवाहरात, प्लॉट मकान दुकान दुकान देख विजिलेंस वालों को चक्कर आ गया। ठिकानों पर 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी और 1.62 करोड़ नकद मिले हैं।

फॉरेस्ट रेंजर के यहां 4 मंजिला मकान, कैश-गहने मिले

भुवनेश्वर। ओडिशा विजिलेंस ने केंद्रापड़ा फॉरेस्ट रेंज के फॉरेस्ट रेंजर रवींद्र कुमार नायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 4 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तलाशी के दौरान 2 लाख 14 हजार नकद मिले हैं। इसके अलावा लगभग 43 लाख की जमा राशि का भी पता चला है। अन्य वित्तीय निवेशों की जांच अभी जारी है। टीम सोने के आभूषणों का वजन और मूल्यांकन भी कर रही है। एक ग्रैंड विटारा और एक दोपहिया वाहन भी मिला है।

चढ़ावा चोरी पर गोपाल राव ने कहा

मैं पद पर बना हूं, मंदिर प्रशासक पद से हटाने की सूचना मात्र अफवाह

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में विवाद में प्रशासक गोपाल राव की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच अफवाह उड़ी कि राव को प्रशासक की भूमिका से हटा दिया गया है। बुधवार को वैदेही भवन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी से मुलाकात की। उन्हें रदान चोरी मामले के बाद लिस्ट से हटाने का मामला गरमाया था। अब उन्होंने इस प्रकार की अफवाहों पर विराम लगाया है।

मीडिया में खबरें गलत चल रहीं

कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी से मीटिंग के बाद राव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर हटाने और प्रशासक की भूमिका से मुक्ति पर कहा मैं पद पर बना हुआ हूं और मैं यहीं रहूंगा। मीडिया में चल रही तमाम अफवाहें गलत हैं।

पंजाब विवाद पर बोले बघेल

यह गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं, हम नियुक्त अध्यक्ष को नहीं हटाएंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने प्रदेश में पार्टी के नेतृत्व में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे फैसले 'गुड्डे-गुड़ियों का खेल' नहीं हैं, जिन्हें बार-बार बदला जाए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व पर आलाकमान का फैसला अंतिम है। वे जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे।

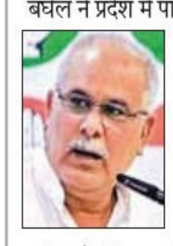

अब फैसले में नहीं होगा कोई बदलाव

मोहाली में चन्नी की मौजूदगी में कई नेताओं ने बैठक की थी। वडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले पर पुनर्विचार की अटकलों को खारिज करते हुए बघेल ने कहा कि जब आलाकमान ने फैसला कर लिया है तो उसे बदला नहीं जाता है।

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

रा०प्र०क०ब-121/2025-26

ग्राम - तोनी/भेडरी तहसील राजपुर

ईश्तहार

एत्द द्वारा सर्वसाधारण आम जनता तोनी को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमति फुलबासो पति केरे जाति कोड़ाकू निवास ग्राम तोनी थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अपने बड़े पिता स्व. करमू आ० स्व. भूलन का मृत्यु दिनॉक 04/04/2022 को मृत्यु हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिनः के माध्यम से पेशी तिथि 22/07/2026 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर काई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

रा०प्र०क०. ब-121/2025-26

ग्राम - तोनी/भेडरी तहसील राजपुर

ईश्तहार

एत्द द्वारा सर्वसाधारण आम जनता तोनी को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमति फुलबासो पति केरे जाति कोड़ाकू निवास ग्राम तोनी थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अपने पिता स्व. सम्पत आ० स्व. भूलन का मृत्यु दिनोंक 06.07.2019 को मृत्यु हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 22/07/2026 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर आई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक. 09/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

रा०प्र० क०/ब-121/2025-26

ग्राम - तोनी/भेडरी तहसील राजपुर

ईश्तहार

एत्द द्वारा सर्वसाधारण आम जनता तोनी को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमति फुलबासो पति केरे जाति कोड़ाकू निवास ग्राम तोनी थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अपने बड़े पिता स्व. बड़े सोमा आ० स्व. भूलन का मृत्यु दिनाँक 08/03/2016 को मृत्यु हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 22/07/2026 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति देश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर काई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 09/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

रा०प्र०क०ब-121/2025--26

ग्राम - तोनी/भेडरी तहसील राजपुर

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण आम जनता तोनी को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमति फुलबासो पति केरे जाति कोड़ाकू निवास ग्राम तोनी थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अपने बड़े पिता स्व. अकला आ० स्व. मूलन का मृत्यु दिनाँक 25/05/2011 को मृत्यु हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 22/07/2026 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति देश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक. 09/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/अ-27/2024-25

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दशराय पिता मंजीत व अन्य, निवासी ग्राम पोडीखुर्द, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम पोडीखुर्द स्थित खसरा नंबर 270, 326, 327, 329, 350, 368, 370/1, 379, 408, 409 रकबा क्रमशः 0.340, 0.741, 2.023, 1.060, 0.401, 0.849, 0.340, 0. 729, 0.081, 0.016 हे. भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/2 अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 20/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका शंकर तिवारी आ०/पति ओम प्रकाश तिवारी जाति निवासी इमलीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-इमलीपारा, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3017/1, 3020 रकबा 455, 0.03 वर्गफीट, एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 03/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः 18/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०/अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक सर्वानन्द दुबे आ० राम इकबाल दुबे, जाति ब्राम्हण, निवासी रवि त्रिपाठी गली, ब्रम्ह रोड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर-02 मोहल्ला सत्तीपारा, नेहरू वार्ड, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 671/16 रकबा 2128 वगफीट भूमि को अनावेदक/केता कविता पेशवानी पति दौलत पेशवानी, निवासी महाराजा गली अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, चंचला कुमार पति संतोष कुमार गुप्ता, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ०ग० के पास बिकय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 16/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एच न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका निवासी सत्तीपारा, जगदीश प्रसाद बारी आ०/पति स्व० रामसुन्दर बारी जाति अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-सत्तीपारा, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 621/2, 622/2 रकबा 0.07 3/4, 0.06 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी,
अम्बिकापुर

कलेक्टर की पहल से कुछ घंटों में बना पिता का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बेटी का तय हुआ एकलव्य में एडमिशन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास के त्वरित हस्तक्षेप और समाज कल्याण विभाग की सक्रिय पहल से ग्राम लोखंडी, पोस्ट जशपुर निवासी दिव्यांग अश्विन लकड़ा का दिव्यांगता प्रमाण पत्र मात्र कुछ ही घंटों में जारी कर दिया गया। इससे उनकी पुत्री श्रुति लकड़ा का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु काउंसलिंग समय पर पूरी हो सकी और उसका प्रवेश सुनिश्चित हो गया। अश्विन लकड़ा ने कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनकी पुत्री श्रुति लकड़ा का एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन हुआ है। काउंसलिंग के दौरान विद्यालय द्वारा उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मांग की गई, जबकि काउंसलिंग की अंतिम तिथि 6 जुलाई थी। समय कम होने के कारण उन्होंने तत्काल सहायता की मांग की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने उपसंचालक, समाज कल्याण धर्मेन्द्र कुमार साहू को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही समाज कल्याण विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निराकरण शुरू किया। जांच में पाया गया कि अश्विन लकड़ा लकवा से दिव्यांग हैं तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ द्वारा उनके लिए दो वर्ष की अवधि का अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मूल्यांकन किया जा चुका था। लेकिन यूडीआईडी पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण अस्थायी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में राज्य स्तरीय यूडीआईडी समन्वयक से समन्वय स्थापित कर तकनीकी समस्या का समाधान कराया गया। साथ ही ऑपरेटर परिवर्तन के कारण ओटीपी संबंधी समस्या भी सामने आई, जिसके निराकरण के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा तत्काल संचालनालय को पत्र प्रेषित किया गया। आवश्यक तकनीकी सुधार के बाद मात्र दो घंटे के भीतर अश्विन लकड़ा का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध होने से उनकी पुत्री श्रुति लकड़ा की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई और उसे प्रवेश मिल गया।इस त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न अश्विन लकड़ा ने कलेक्टर एवं समाज कल्याण विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिली प्रशासनिक सहायता से उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सका।

सुरक्षा कंपनी एसआईएस लिमिटेड में की जाएगी 150 सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। भारत की अग्रणी सुरक्षा कंपनी एसआईएस लिमिटेड द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के स्नातक बेरोजगार युवाओं के लिए 150 जीटीओ सुरक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर भर्ती की जाएगी। चयन प्रक्रिया 11 जुलाई से 14 जुलाई तक भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली एवं ग्लोबल इंडिया स्किल डेवलपमेंट की तरफ से एस.आई.एस. के संयुक्त तत्वाधान में पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत एसआईएस प्रशिक्षण केन्द्र, लाइवलीहुड महाविद्यालय, बॉयज छात्रावास, डोडकाचौरा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। एसआईएस के कमांडेंट श्री कुमार शिवेन्द्र ने बताया कि अभ्यर्थी का स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर एवं आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण के दौरान ही अभ्यर्थियों को 33 हजार से 40 हजार रुपये समग्र लागत वेतन प्रति माह दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को पेंशन, उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह बीमा, चिकित्सा, आवास, दो बच्चों को भारतीय पुलिस सेवा विद्यालय देहरादून में शिक्षा की सुविधा, अंश वितरण, यात्रा भत्ता एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नियुक्ति संपूर्ण भारत स्तर पर सभी स्थानों पर प्रदान की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी ४४ल्र्ल्र्ीं एवं जॉब एट एसआईएस फेसबुक पेज के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की त्वरित पहल से दूर हुई प्रेमनगर की लो-वोल्टेज समस्या

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की त्वरित पहल से पत्थलगांव के प्रेमनगर मोहल्ले में लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान कर दिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रेमनगर के रहवासियों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय को अवगत कराया था कि पूरे मोहल्ले में केवल एक ही ट्रांसफार्मर होने के कारण पिछले तीन दिनों से लगातार लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई थी। इसके चलते घरों में लगे विद्युत उपकरण ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे थे। वहीं, कुओं और बोरवेल की मोटरें भी बंद पड़ी थीं, जिससे पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था और लोगों को दैनिक उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश पर विद्युत विभाग की टीम ने कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया। इसके बाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो गई तथा लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया। समस्या के त्वरित निराकरण पर प्रेमनगर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर की गई पहल से न केवल बिजली की समस्या दूर हुई, बल्कि पेयजल संकट से भी राहत मिली है। लोगों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही की सराहना करते हुए इसे जनसमस्याओं के प्रभावी समाधान का उदाहरण बताया।

09 जुलाई को जिले में हुई 46.4 मिमी औसत वर्षा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिले में 01 जून से 09 जुलाई 2026 तक 2081.4 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 09 जुलाई तक सामान्य औसत वर्षा 2789.3 मिमी हुई है। बीते दिवस जिले में 46.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसीलवार वर्षा इस प्रकार है - तहसील जशपुर में 191.5 मिमी, मनोरा में 307.8 मिमी, कुनकुरी में 253.7 मिमी, दुलदुला में 176.0 मिमी, फरसाबहार में 129.0 मिमी, बगीचा में 152.0 मिमी, कांसाबेल में 205.5 मिमी, पत्थलगांव में 226.4 मिमी, सन्ना में 291.3 मिमी एवं बागबहार में 148.2 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा मनोरा तहसील में 307.8 मिमी दर्ज की गई है। 09 जुलाई को सर्वाधिक पत्थलगांव तहसील में 9.3 मिमी वर्षा हुई।

कलेक्टर ने किया सीएचसी कांसाबेल का निरीक्षण

साफ-सफाई, आधार बेस हाजिरी और बेहतर इलाज के दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर रोहित व्यास लगातार स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांसाबेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों तथा मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं की विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर व्यास ने सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों

को समय पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए भी निर्देशित किया।

कलेक्टर व्यास ने अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अस्पताल परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही अस्पताल भवन में जहां भी सीपेज को ठीक करने अथवा अन्य मरम्मत कार्य की आवश्यकता हो, उसका प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की खराब पड़ी एक एम्बुलेंस को शीघ्र मरम्मत कर पुनः संचालन में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। उन्होंने अस्पताल भवन, शौचालय एवं पूरे परिसर की नियमित साफ-सफाई बनाए रखने को कहा। साथ ही अनुपयोगी एवं कबाड़ में पड़े सामानों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. एस.आर. टोप्पो, तहसीलदार श्रीमती आस्था चंद्राकर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप मरावी, डीपीएम राजीव रंजन मिश्रा सहित अस्पताल के चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

फर्जी ई-चालान लिंक से सावधान, सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर ही करें भुगतान

जशपुरनगर। साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी ई-चालान के एसएमएस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठगने की घटनाएं सामने आने पर जिला परिवहन अधिकारी ने जन जागरूकता हेतु अपील की गई है। वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा आम नागरिकों को भ्रमित करने के उद्देश्य से फर्जी ई-चालान के भ्रामक लिंक भेजे जा रहे हैं। इन लिंक के माध्यम से नागरिकों की बैंकिंग एवं अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त कर साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। भारत सरकार के आधिकारिक ई-चालान पोर्टल पर भी नागरिकों को ऐसे फर्जी पोर्टलों एवं संदेशों से सावधान रहने की चेतावनी प्रदर्शित की गई है। आमजन को साइबर ठगी से सुरक्षित रखने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से आधिकारिक ई-चालान पोर्टलँ ३३स्त्र२://ीूँं्हिंल्ल.स्त्रं१५ँल्ल.ॅङ्म५.ल्ल अथवा संबंधित राज्य पुलिस/परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट/मोबाइल ऐप के माध्यम से ही भुगतान करने की अपील की गई है।

योगिनी एकादशी, आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का संदेश देता आषाढ़ का पावन पर्व

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। भारतीय संस्कृति में व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का उत्सव है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी इसी सनातन परंपरा का दिव्य पर्व है। यह भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना का दिन है, किन्तु इसका वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करना है।

पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। यह संख्या केवल गणना नहीं, बल्कि व्रत की आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। भारतीय दर्शन का मूल संदेश है - ₹आत्मानं विद्धि₹ अर्थात स्वयं को जानो। उपनिषदों का उद्घोष है - ₹तत्त्वमसि₹ अर्थात ₹तुम वही परम सत्य हो।₹ योगिनी एकादशी का व्रत इसी आत्मबोध की ओर बढ़ने का अभ्यास है। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं - ₹उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत।₹ अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए।

गीता में ही कहा गया है - ₹युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।₹ जिसका आहार-विहार, कर्म और विश्राम संतुलित है, वही योगी दुःखों से मुक्त होता है। कठोपनिषद् में मानव शरीर की तुलना रथ से की गई है - इन्द्रियाँ घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। योगिनी एकादशी इसी संयम का अभ्यास कराती है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। योगिनी एकादशी चरित्र निर्माण का आध्यात्मिक साधन है। महात्मा गांधी के लिए उपवास केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि सत्य, आत्मसंयम और नैतिक शक्ति का अभ्यास था।

पद्म पुराण में वर्णित हेममाली की कथा सिखाती है कि कर्तव्य की उपेक्षा पतन की ओर ले जाती है, जबकि पश्चाताप, संयम और ईश्वर-भक्ति पुनः सम्मान दे सकते हैं। आज समाज मानसिक तनाव, पारिवारिक विघटन और नैतिक भ्रम से जूझ रहा है। ऐसे में योगिनी एकादशी सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख उपभोग में नहीं, संयम में है; संग्रह में नहीं, सेवा में है। भारतीय संस्कृति कहती है - ₹सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।₹ योगिनी एकादशी केवल व्यक्तिगत मोक्ष का नहीं, बल्कि समाज के कल्याण, करुणा, दान और सद्भाव का भी संदेश देती है। इस योगिनी एकादशी पर केवल अन्न का नहीं, बल्कि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, असत्य, हिंसा और अहंकार का भी त्याग करें।

स्वास्थ्य सेवाओं पर कलेक्टर सख्त, सर्पदंश-रेबीज का तत्काल नि:शुल्क इलाज हो, एचपीवी टीकाकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य करें पूरा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं, संस्थागत प्रसव, एचपीवी टीकाकरण, सिकलसेल, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, एनसीडी, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक प्रभावी, सुलभ एवं जन-केंद्रित बनाते हुए प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य, समस्त नोडल अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम, बीडीएम, परियोजना अधिकारी एवं मितानिन समन्वयक मौजूद रहे।

102, 108 और 1099 एम्बुलेंस सेवाएं हर समय रहें सक्रिय

कलेक्टर व्यास ने 102, 108 एवं 1099 एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए इन्हें हर समय सक्रिय एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस सेवा मरीजों के लिए जीवन रक्षक की भूमिका निभाती है, इसलिए इनके संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक माह की 9 एवं 24 तारीख को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में स्वास्थ्य जांच के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को 102 एम्बुलेंस के माध्यम से सुरक्षित रूप से वापस उनके घर तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।

पीवीटीजी बसाहटों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट

कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से पीवीटीजी बसाहटों के अलावा अन्य जरूरतमंद बसाहटों में भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर मेले आयोजित होते हैं अथवा पांच हजार से अधिक लोगों की आमसभा या बड़ा आयोजन होता है, वहां भी मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

अस्पताल से छुट्टी से पहले नवजात को मिले जन्म प्रमाण-पत्र

कलेक्टर ने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म लेने वाले बच्चों का अस्पताल से छुट्टी होने से पहले ही जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे नवजात बच्चों का समय पर आधार कार्ड बन सकेगा और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने सभी संस्थागत प्रसव के मामलों में जननी सुरक्षा योजना की राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि पात्र माताओं को योजना का लाभ बिना किसी अनावश्यक विलंब के मिल सके।

सर्पदंश और रेबीज के मरीजों को मिले तत्काल नि:शुल्क उपचार

बरसात के मौसम में सर्पदंश एवं कुत्ते के काटने से रेबीज के खतरे को देखते हुए कलेक्टर ने सभी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रैबीज वैक्सीन सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्पदंश अथवा कुत्ते के काटने से संबंधित मरीज अस्पताल पहुंचने पर उन्हें तत्काल एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए।

गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक में बताया गया कि गर्भवती महिलाओं का अनुपातिक लक्ष्य के विरुद्ध 71 प्रतिशत पंजीयन हुआ है, जिसमें प्रथम तिमाही में 92 प्रतिशत पंजीयन तथा 92 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की चार एएनसी जांच पूरी हुई है। कलेक्टर ने सभी गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन आरसीएच पोर्टल पर ऑनलाइन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर एएनसी पंजीयन, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं, शिशु पंजीयन एवं टीकाकरण से संबंधित आंकड़ों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने श्रीचिंग एवरी डिलीवरीश (रेड) कॉल सेंटर के माध्यम से गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के मोबाइल नंबरों के सत्यापन की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पत्थलगांव में 141 असफल कॉल सामने आने पर उन्होंने आरसीएच पोर्टल में गर्भवती महिला का स्वयं का अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का सक्रिय मोबाइल नंबर ही दर्ज करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरत के समय उनसे आसानी से संपर्क किया जा सके और आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराया जा सके।

14 वर्ष पूर्ण कर चुकी बालिकाओं का शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण हो

कलेक्टर ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी पात्र बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अभिभावकों की प्रभावी काउंसलिंग करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं को समय पर टीका लगाकर भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे से सुरक्षित किया जा सके।

सिकलसेल, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया और आयुष्मान सहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा

बैठक में सिकलसेल, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी), ओरल हेल्थ, आईडीएसपी, नियमित टीकाकरण, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) और आयुष्मान कार्ड सहित सभी प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला अस्पताल के एमसीएच भवन में सीपेज की समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया गया। कलेक्टर ने एमसीएच भवन सहित अन्य स्वास्थ्य भवनों में जहां भी सीपेज की समस्या है, उनका निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालयीन कार्यों को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित करने को कहा। उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्यप्रणाली से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने के साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी मजबूत होगी।

जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी पहचान : अरुण देव

0 पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ ने किया जिले का आकस्मिक दौरा
0 अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था व बेहतर पुलिसिंग के दिए निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के द्वारा विगत दिनों जिले का औचक दौरा कर पुलिस राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई। वहीं कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, बीट पुलिसिंग की गुणवत्ता सहित अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा करते हुए एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर से जिले की गतिविधियों, प्रमुख विषयों एवं बेहतर पुलिसिंग की रणनीति के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान आईजी सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा भी मौजूद रहे।

बैठक में डीजीपी अरूण देव गौतम ने कहा कि पुलिस की सबसे बड़ी पहचान जनता का विश्वास है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी, संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ करना चाहिए। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा आम

नागरिकों के प्रति सहयोगात्मक एवं मानवीय व्यवहार ही प्रभावी पुलिसिंग की पहचान है। महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ फौरन कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की विशेष प्राथमिकता है। आमजनता से प्राप्त होने वाली छोटी-बड़ी शिकायतों पर फौरन एक्शन ली जाए और उनके साथ संवेदनशील होकर विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए। उन्होंने अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी गश्त, मुखबिर तंत्र को मजबूत करने, आदतन अपराधियों की सतत निगरानी रखने तथा तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर विशेष बल दिया।

बैठक में जिले की वर्तमान कानून-व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति, अपराधों की रोकथाम, लंबित प्रकरणों के निराकरण, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की समीक्षा, मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सामुदायिक पुलिसिंग, डायल-112 की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न अभियानों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आधुनिक संसाधनों से युक्त पुलिस अधोसंरचना पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आमजन को बेहतर एवं त्वरित पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

डीजीपी श्री गौतम ने अपराधों के निकाल पर जोर देते हुए कहा कि माननीय न्यायालय में पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की पेशी शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराई जाए। गंभीर अपराध के मामलों में सजा की दर की जानकारी ली जो सजा की दर बेहतर होने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने बेसिक पुलिसिंग के मूल सिद्धांतों, प्रभावी अपराध नियंत्रण, वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना, घटनास्थल संरक्षण, भौतिक एवं डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण, अभियोजन की सफलता बढ़ाने के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन, सीएसपी बेनार्ड कुजूर, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, डीएसपी अजाक रीता नीलम कुजूर, एसडीओपी प्रतापपुर अनूप एक्का मौजूद रहे।

मंत्री नेताम 10 जुलाई को विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल

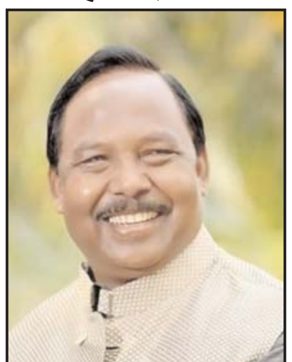

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम 10 जुलाई 2026 को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा जिले में संचालित गतिविधियों की समीक्षा करेंगे।

मंत्री श्री नेताम प्रातः 11 बजे रामानुजगंज में शाला प्रवेश उत्सव तथा स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तत्पश्चात् शाम 5 बजे मंत्री श्री नेताम की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में जिला खनिज न्यास निधि की बैठक आयोजित होगी।

शहर के बड़ा एवं छठ तालाब में चलेगा विशेष स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ''जन सहयोग से स्वच्छ सूरजपुर'' अभियान के तहत शनिवार को नगर के बड़ा तालाब एवं छठ तालाब में विशेष स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से नगर के प्रमुख जलाशयों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की दिशा में सामूहिक प्रयास किया जाएगा।

अभियान का संचालन नगर पालिका परिषद की टीम द्वारा किया जाएगा। इस दौरान जनसहभागिता के माध्यम से दोनों तालाबों एवं उनके आसपास के क्षेत्र की व्यापक साफ-सफाई की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नगर के प्रमुख जलाशयों को स्वच्छ बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं सामूहिक सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन ने नगर के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी बंधुओं, युवाओं, विद्यार्थियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में शामिल होकर श्रमदान करें एवं जन सहयोग से स्वच्छ सूरजपुर कि संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। नपा ने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे शनिवार को प्रातः 7 बजे बड़ा तालाब एवं छठ तालाब स्थल पर उपस्थित होकर श्रमदान में सहभागी बनें तथा स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ सूरजपुर के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें।

द्वितीय अवसर परीक्षा, कक्षा 10वीं गणित परीक्षा का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा वर्ष-2026 का औचक निरीक्षण सहायक संचालक शिक्षा अजय कुमार सिंह एवं व्याख्याता रामकुशल तिवारी व श्रीमती शशिकला दुबे द्वारा कन्या एवं बालक सूरजपुर का औचक निरीक्षण किया गया। गुरुवार को कक्षा 10 वीं, गणित की परीक्षा कन्या एवं बालक में परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या 130 में से 128 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए जबकि 02 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या-275 में से 256 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए जबकि 19 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

अवैध खनिज परिवहन पर 6 वाहन जब्त

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनि अमला एवं जिला स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाकर बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 8 जुलाई को खनिज अमला द्वारा छठघाट से सरस्वतीपुर मार्ग पर वाहन जांच के दौरान खनिज गिट्टी से भरी एक हाइवा बिना अभिवहन पास के परिवहन करते हुए पाई गई। उक्त वाहन को खनिज सहित जब्त कर पुलिस

चौकी बसदेई की अभिरक्षा में रखा गया है।

इसी प्रकार कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 09 जुलाई को तहसील प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम खड़गंवाकला में डम्पयार्ड से बिना अभिवहन पास के खनिज रेत का परिवहन करते हुए कुल पांच टिपर वाहनों को जब्त किया गया। सभी प्रकरणों में अवैध खनिज परिवहन का मामला दर्ज कर वाहनों को पुलिस चौकी खड़गंवाकला के सुपुर्द किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। खनि अमला एवं जिला स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा खनिज प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बेहतर उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को महत्वपूर्ण सलाह

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। खरीफ सीजन के दृष्टिगत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर नर्सरी तैयार होने की स्थिति में रोपाई करें अथवा अंकुरित बीजों की लेही विधि, ड्रम सीडर अथवा छिटकवा विधि से धान की बुवाई करें। बुवाई एवं रोपाई से पहले बीजों का कवकनाशी (कार्बेन्डाजिम) एवं जैव उर्वरकों से उपचार करने की भी सलाह दी गई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हरेली तिहार तक खरीफ फसलों की बुआई एवं रोपाई की जा सकती है। जमीन में बतर की स्थिति में 15 जुलाई तक धान की बुवाई कर लें। रोपाई या बियासी पद्धति से धान की खेती करने वाले किसान 30 जुलाई तक रोपाई या बियासी का कार्य कर लें।

स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण रूप में लागू कर दिए निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं, अधोसंरचना विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं आमजन

के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएचओ, सिविल सर्जन सहित सभी बीएमओ और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।बैठक में कलेक्टर ने सीजीएमएससी के माध्यम से जिले में संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर अस्पताल भवनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश भी दिए।कलेक्टर ने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रसव सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मितानिनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिले के अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता तथा रिक्त पदों की जानकारी ली। उन्होंने सभी बीएमओ, बीपीएम, बीटीओ एवं सुपरवाइजरों को नियमित रूप से फील्ड विजिट कर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करने तथा अपने क्षेत्र में संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिले में मौसमी बीमारियों, सर्पदंश (स्नेक बाइट) एवं डॉग बाइट की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों, एंटी-स्नेक वेनम, एंटी-रेबीज वैक्सीन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। उन्होंने 16 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विशेष महाअभियान के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड एवं आभा कार्ड बनाने के कार्य में सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए शत-प्रतिशत आधार आधारित उपस्थिति लागू करने के निर्देश भी दिए।प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने उच्च जोखिम गर्भावस्था के मामलों की नियमित निगरानी कर गर्भवती महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में नियमित टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी पात्र बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा उसकी समयबद्ध ऑनलाइन पोर्टल एंट्री करने के निर्देश दिए।

इस दौरान कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने एनआरसी में भर्ती बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उपचार, पौष्टिक आहार एवं समुचित देखभाल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

कमांक/5174/भण्डार/2026 — अम्बिकापुर दिनांक 06/07/2026

निविदा विज्ञप्ति

वर्ष 2026–2027 के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा औषधि, सर्जिकल उपकरण, रसायन, प्रयोगशाला सामग्री एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं एवं उनके अधिकृत विक्रेताओं/सप्लायर से, जिनके पास थोक विक्रेता ड्रग लाईसेंस एवं पेन नम्बर व छत्तीसगढ़ का जीएसटी नम्बर हो, से मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र/शर्ते एवं अन्य जानकारी नतहनरं.हवअ.पद से अथवा जिला औषधि भण्डार, अम्बिकापुर से प्राप्त की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 05.08.2026 समय 03 बजे शाम तक होगी। निविदा खोलने की तिथि 05.08.2026 समय 04 बजे शाम।

1. निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की तिथि – 07.07.2026 से
2. निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि – 05.08.2026 शाम 03 बजे तक
3. निविदा खुलने की तिथि – 05.08.2026 शाम 04 बजे से

नोटः– निविदा खोलने कि तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

जी-262701962/1

जिले में नशे से बचाव हेतु पुलिस का ऐतिहासिक आयोजन, 70 हजार लोगो ने ली नशे से दूर रहने की शपथ

कलेक्टर व डीआईजी ने नशे को ना, जिंदगी को हॉ कहने दिलाई शपथ

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से सूरजपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान ''नवजीवन'' के अंतर्गत जिलेभर के गांव, पंचायत भवनों, स्कूल-कालेजों एवं विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में व्यापक स्तर पर शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के दौरान 69.218 ग्रामीणों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, युवाओं, महिलाओं एवं आम नागरिकों ने नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रेना जमील एवं डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने भी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व लोगों को नशे से बचाव को लेकर शपथ दिलाई और नशे से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला।

नशे से बढ़ती है आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं : रेना जमील

कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर सूरजपुर श्रीमती रेना जमील ने कहा कि एसएसपी श्री ठाकुर के निर्देशन में एक ही दिन में जिले के सभी ग्रामों, स्कूलों, कालेजों में नशे से बचाव को लेकर शपथ का महाअभियान नवजीवन का आयोजन सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक जीवन और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। नशे की लत न केवल शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाती है, बल्कि इससे आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ती हैं। कलेक्टर ने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा लगाएं तथा समाज में जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का महाअभियान : प्रशांत

एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने बताया कि 7 जुलाई को जिले के समस्त थाना-चौकी प्रभारी, पुलिस अधिकारी व जवानों के द्वारा जिलेभर में 509 स्थानों जिनमें पंचायत भवन, स्कूल-कालेज सहित विभिन्न स्थल शामिल है उन सभी जगहों पर 69,218 ग्रामीणों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं एवं आम नागरिकों को नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई है। एसएसपी ने कहा कि नशे के विरुद्ध नवजीवन अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का महाअभियान है। उन्होंने कहा यदि इस अभियान के माध्यम से हम कुछ लोगों को भी नशे की लत से बचाने में सफल हो जाते हैं, तो हमारा यह प्रयास सार्थक और सफल साबित होगा। उन्होंने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधि, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से अपील की कि वे नशा मुक्त समाज के निर्माण में पुलिस का सहयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें।

थाना कोतवाली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन ने स्कूली बच्चों को नशे से बचाव के लिए नशे को ना, जिंदगी को हा करने की शपथ दिलाई। जिले समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना-चौकी प्रभारी व पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर नशे से बचाव की शपथ दिलाई और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। उपस्थित लोगों को बताया कि नशा व्यक्ति को धीरे-धीरे कमजोर करता है और उसके जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए समय रहते इससे दूरी बनाना आवश्यक है। कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे, अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे।

थाना प्रतापपुर रहा अव्वल

एसएसपी ने बताया कि नशे से बचाव के इस महाअभियान में थाना प्रतापपुर के द्वारा सबसे ज्यादा 59 स्थानों पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं थाना झिलमिली द्वारा 58 तथा थाना भटगांव 48 शपथ कार्यक्रम कराते हुए क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे।

निरंतर होंगे ऐसे आयोजन

एसएसपी ने बताया गया कि नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से जनसंवाद, जागरूकता कार्यक्रम, चलित थाना, पुलिस जन चौपाल, रैली एवं शपथ समारोह आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि नशे के विरुद्ध इस महाअभियान में सहभागी बनें तथा स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

अधिवक्ता संघ ने भी ली शपथ

मंगलवार को नवजीवन महाअभियान में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बलराम शर्मा सहित कई अधिवक्ताओं ने नशे से दूरी बनाने की शपथ ली और पुलिस के इस पहल में हरसंभव सहयोग देने की बात कही।

सरगुजा फ्रंटलाइन

संपर्क करें
समाचार, इश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

आयुष्मान में पंजीयन नहीं, फिर भी भर्ती और वसूली का आरोप

संभागीय संयुक्त संचालक ने एचआर हेल्थकेयर का जांच करने का दिया है निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में एचआर हेल्थकेयर का आयुष्मान भारत योजना में पंजीयन नहीं होना सामने आया है, इसके बावजूद अस्पताल पर आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों को भर्ती करने और कथित रूप से योजना का लाभ उठाने के आरोप लगे हैं। मामले में संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने विस्तृत जांच के निर्देश देते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. डी.के. सोनी ने इसकी शिकायत की थी। संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने एचआर हेल्थकेयर में चल रहे आयुष्मान के गोरखधंधे की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया था। 6 जुलाई को सीएमएचओ द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि एनएच गोयल हॉस्पिटल का आयुष्मान भारत योजना में पंजीयन ही नहीं है। यदि अस्पताल का पंजीयन नहीं

है तो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों की भर्ती कैसे की गई, इसकी गहन जांच की जाएगी। जांच में यह सामने आता है कि आयुष्मान योजना के नाम पर राशि निकाली गई है या मरीजों से अवैध वसूली की गई है, तो इसे गंभीर अनियमितता माना जायेगा। उन्होंने कहा है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जिले के सभी निजी अस्पतालों को चेतावनी दी गई है कि वे आयुष्मान योजना के नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि, आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. डीके. सोनी के पास कई ग्रामीणों ने एचआर हेल्थकेयर में इलाज कराने के बाद आयुष्मान कार्ड से पूरी राशि निकालने की शिकायत की है, जबकि उन्हें न तो कोई मेडिकल रिपोर्ट दी गई और न ही इलाज का बिल उपलब्ध कराया गया। शिकायतों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग से जांच की मांग उन्होंने की थी। मामले की पड़ताल के दौरान जनपद पंचायत राजपुर, जिला बलरामपुर के ग्राम कोदौरा के कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शैलेश गुप्ता नामक व्यक्ति गांव के लोगों को मुफ्त इलाज का भरोसा देकर एचआर हेल्थकेयर में उन्हें कथित रूप से भर्ती कराता था। ग्रामीणों के अनुसार वह अपनी गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले जाता और कुछ दिनों बाद वापस गांव में छोड़ देता था। इलाज के बाद उन्हें न कोई मेडिकल रिपोर्ट दी गई और न ही कोई बिल उपलब्ध कराया गया।

एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी

डॉ. डी.के. सोनी के अनुसार, ग्रामीणों का दावा है कि ग्राम कोदौरा में ही लगभग 15 ऐसे मरीज हैं, जिनके आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया गया। इनका कहना है कि यदि अन्य गांवों में भी जांच की जाए तो ऐसे कई और मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि, संबंधित दस्तावेजों के आधार पर वे अस्पताल संचालकों एवं संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि मामले की जांच के बाद ही होगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही जांच के संबंध में एचआर हेल्थकेयर प्रबंधन की ओर से अस्पताल का पक्ष सामने नहीं आया है।

> मैंने सीएमएचओ को इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे। 6 जुलाई को प्राप्त जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि एचआर हेल्थकेयर का आयुष्मान भारत योजना में पंजीयन नहीं है। यदि बिना पंजीयन के आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों की भर्ती की गई है या योजना की राशि निकाली गई है, तो यह गंभीर मामला है। इसकी सूक्ष्मता से जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखा जा रहा है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी निजी अस्पतालों को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसी अनियमितताओं से बचें।
>
> **डॉ. अनिल कुमार शुक्ला, संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा**

विवाह के ढाई माह बाद नवविवाहिता ने कर लिया जहर सेवन, इलाज दौरान मौत

मायके पक्ष ने पति पर मानसिक प्रताड़ना सहित लगाया गंभीर आरोप

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। विवाह के महज ढाई माह बाद एक नवविवाहिता ने जहर सेवन करके आत्महत्या कर ली, उसे होलीक्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मायके पक्ष ने पति पर दूसरी युवती से बातचीत करने, जान से मारने की धमकी देने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं पति ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि पत्नी अलग मोबाइल फोन की मांग को लेकर नाराज थी, इसी गुस्से में उसने जहर खा लिया।

जानकारी के मुताबिक, मृतिका आकृति पटेल की शादी 20 अप्रैल को बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र के ग्राम इंजानी निवासी सुशील पटेल से प्रेम विवाह के रूप में, सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। मृतका की मां सुषमा पटेल व पिता श्रवण पटेल ने अपने बयान में बताया है कि शादी के करीब एक माह बाद आकृति ने फोन करके बताया था कि उसका पति किसी दूसरी लड़की से बात करता है। जब वह इसके बारे में पूछती थी तो कोई जवाब में जान से मारने की धमकी मिलती थी। पति का मोबाइल खराब होने पर उसने आकृति का मोबाइल अपने पास रख लिया, जिससे वह मायके वालों से भी बात नहीं कर पा रही थी।

मृतका की मां ने बताया कि 3 से 6 जुलाई तक उनकी बेटी से कोई बातचीत नहीं हुई। 7 जुलाई को समधन से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि मोबाइल और दूसरी लड़की से बातचीत को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है। करीब 15 मिनट बाद दामाद सुशील ने फोन करके बताया कि आकृति दवाई खा ली है। परिजन तत्काल इंजानी के लिए निकले, लेकिन रास्ते में पता चला कि आकृति को वाड्रफनगर अस्पताल से अंबिकापुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मायके पक्ष का कहना है कि उपचार के दौरान उल्टी में सल्फास का तेज गंध आ रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे होलीक्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां 8 जुलाई को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

मोबाइल खरीदकर देने कर रही थी जिद्द

मृतका के पति सुशील पटेल ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि 7 जुलाई की सुबह उसकी सास का फोन आया था, उसने पत्नी से बात करने के लिए कहा, लेकिन आकृति ने बात करने से इन्कार करते हुए कहा कि उसे अलग मोबाइल चाहिए। उसने बाद में नया मोबाइल फोन खरीदकर देने और अभी इसी मोबाइल का इस्तेमाल कर लेने के लिए कहा था। सुशील के अनुसार वह घर के बाहर काम करने चला गया। कुछ देर बाद पत्नी उल्टी करते हुए बाहर आई। उल्टी में सल्फास का आधा घुला गोली नजर आया। पूछने पर उसने इशारे से दो गोली खाना बताया।

धान की फसल में समय पर खरपतवार प्रबंधन से बढ़ेगी उत्पादकता

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. संदीप शर्मा ने किसानों को वैज्ञानिक तकनीक अपनाने दी सलाह

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। खरीफ मौसम में धान की फसल से अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए समय पर खरपतवार प्रबंधन अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति एवं निदेशक विस्तार के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा द्वारा किसानों को धान की फसल में वैज्ञानिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के उपायों की जानकारी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. संदीप शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा होने के साथ-साथ सरगुजा जिले में भी धान का व्यापक रकबा है। ऐसे में धान की अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए खरपतवारों का समय पर एवं वैज्ञानिक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शर्मा ने बताया कि धान की फसल में उगने वाले खरपतवार जल, पोषक तत्व, प्रकाश एवं स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके कारण फसल की बढ़वार प्रभावित होती है तथा उत्पादन में 15 से 80 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि रोपाई के बाद 20 से 45 दिनों की अवधि खरपतवार नियंत्रण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि इस अवधि में खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण कर लिया जाए तो धान की फसल स्वस्थ रहती है तथा उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। धान के खेतों में मुख्य रूप से घास, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तथा नटसेज/मोथा वर्ग के खरपतवार पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति अलग-अलग होने के कारण इनके नियंत्रण के लिए भी वैज्ञानिक एवं संयुक्त प्रबंधन अपनाना आवश्यक है।

सस्य क्रियाएं एवं यांत्रिक उपायों को दें प्राथमिकता

खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले सस्य क्रियाएं अपनाए जाने चाहिए। इसके अंतर्गत खेत की अच्छी तैयारी, गहरी जुताई एवं पलेवा करने से खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं। उचित बीज दर एवं निर्धारित कतार दूरी रखने से फसल सघन होती है, जिससे खरपतवारों की वृद्धि स्वतः कम होती है। इसके अलावा फसल चक्र अपनाने एवं समय पर रोपाई करने से भी खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। डॉ. शर्मा ने बताया कि यांत्रिक विधियों के अंतर्गत रोपाई के 20 से 25 दिन एवं 40 से 45 दिन के बीच हाथ से निराई-गुड़ाई करना अत्यंत लाभकारी होता है। आवश्यकता अनुसार कोनोवीडर का उपयोग भी धान के खेतों में खरपतवार नियंत्रण का प्रभावी एवं कम लागत वाला विकल्प है।

खरपतवारनाशियों का प्रयोग फसल की अवस्था अनुसार करें

वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शर्मा ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवारनाशियों का उपयोग फसल की अवस्था एवं खरपतवार की प्रकृति के अनुसार निर्धारित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि रोपा धान में अंकुरण पूर्व खरपतवार नियंत्रण के लिए पायरेजो सल्फ्युरौन 10 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. (साथी) का 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से रोपाई के 0 से 3 दिनों के भीतर तथा प्रीटिलाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी. (रिफिट) का 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 3 से 6 दिनों के भीतर उपयोग करना लाभकारी होता है। इसी प्रकार बोता धान में अंकुरण पश्चात बिसपायरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत एस.सी. (नोमिनी गोल्ड) का 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 20 से 25 दिनों के भीतर प्रयोग करने की सलाह दी गई है। रोपा धान में अंकुरण पश्चात खरपतवार नियंत्रण के लिए फिनाक्सापॉप+ इथाक्सीसल्फ्युरौन 15 प्रतिशत डब्ल्यू.डी.जी. का 290 ग्राम प्रति एकड़, बिसपायरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत एस.सी. का 100 ग्राम प्रति एकड़ तथा पिनोक्सुलम 21.7 प्रतिशत एस.सी. (ग्रेनाइट) का 42 ग्राम प्रति एकड़ निर्धारित समय पर उपयोग करने से घास कुल, चैड़ी पत्ती वाले एवं मोथा वर्ग के खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है।

वैज्ञानिक सलाह अपनाकर बढ़ाएं उत्पादन

कृषि विज्ञान केन्द्र, सरगुजा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. संदीप शर्मा ने जिले के किसानों से अपील की है वे कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसाओं का पालन करते हुए समय पर एकीकृत खरपतवार प्रबंधन अपनाएं। इससे धान की फसल को खरपतवारों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा, उत्पादन लागत में कमी आएगी, गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त होगी तथा किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

व्यापारी जीएसटी के अनिवार्य नियमों का पालन करें-टैक्स बार एसोसिएशन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने व्यापारियों के प्रतिष्ठान का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इस संदर्भ में टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा की आवश्यक बैठक की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने व्यापारियों को अहम जानकारियां दी। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि, जो व्यापारी जीएसटी नंबर लेकर व्यापार कर रहे हैं वे दुकान के सामने फर्म का नाम, पता, प्रोपराइटर का नाम के साथ जीएसटी नंबर लिखा हुआ बोर्ड लगाएं। जीएसटी प्रमाण पत्र को दुकान में लगा कर रखें। क्रय एवं विक्रय बिल अवश्य रखें, 200 रुपये से ज्यादा मूल्य के विक्रय का बिल अनिवार्य रूप से बनाएं। ई-वे बिल बनाते समय बिल के साथ मिलान कर लें, गाड़ी नंबर के साथ सभी जांच करके ही गाड़ी विक्रय स्थल पर भेजें। बिना बिल के मॉल का क्रय-विक्रय न करें। क्रय एवं विक्रय के समय भुगतान बैंक के माध्यम से करें। उन्होंने कहा कि उपरोक्त नियमों का पालन व्यापारी करेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता एवं सीए उपस्थित हुए।

ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने जप्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण कराया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिले के 15 प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों का 'जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति' के मार्गदर्शन में नष्टीकरण इंद्रा पावर जैन प्राइवेट लिमिटेड नयनपुर गिरवरगंज सूरजपुर में विधिवत किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्य मौके पर उपस्थित रहे।

एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत जप्त मादक के 15 प्रकरणों में गांजा 44.155 किलोग्राम, इंजेक्शन 1478 नग, टेबलेट 2610 नग, कफ सिरफ 110 नग को विधिवत नष्ट किया गया। नष्टीकरण कार्रवाई के दौरान समिति के अध्यक्ष डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल, अन्य सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकान्त गायकवाड़ एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी की गई।

कार्यवाही से पूर्व समस्त प्रकरणों की विस्तृत सूची एवं आवश्यक दस्तावेजों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा नष्टीकरण की सूचना संबंधित विभागों एवं न्यायालय को अग्रिम रूप से दी गई है। नष्टीकरण कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से डीसीआरबी शाखा प्रभारी सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक गंभीर साय, प्रधान आरक्षक अनिल तिर्की, आरक्षक अजय यादव उपस्थित रहे।

आठ जुआरी गिरफ्तार, 50900 रुपये नकद और कार, मोटरसायकल जप्त

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। गांधीनगर थाना पुलिस ने जुआ एक्ट के प्रकरण में कार्रवाई करते हुये आठ आरोपियों के कब्जे से नकद रकम 50 हजार 900 रुपये एवं ताश की गड्डी सहित एक चार पहिया वाहन एवं 4 दोपहिया वाहन जप्त किया है। आरोपित चठिरमा स्वास्तिक ढाबा के परछी में हार-जीत का दांव लगा रहे थे। थाना गांधीनगर पुलिस टीम की पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि, चठिरमा स्वस्तिक ढाबा के परछी में बैठकर कुछ लोग रुपये-पैसे का दांव लगा रहे हैं। पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए ढाबा के पास जाकर घेराबंदी किया। यहां 8 व्यक्ति ताश पत्ती से रुपये-पैसों का हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते मिले, इनके फड और कब्जे से 52 पत्ती ताश, नकद रकम व चार पहिया एवं दोपहिया वाहन पुलिस ने जप्त किया है। आरोपियों के विरूद्ध धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम का मामला कायम करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मारकण्डे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक विवेक चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक अभिषेक दुबे, आरक्षक अमृत सिंह, सैनिक संतोष सक्रिय रहे।

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपित-प्रेम सिंह पिता उमेश सिंह 38 वर्ष निवासी केदारपुर, शंकर मिस्त्री पिता नरेन्द्र मिस्वी 32 वर्ष निवासी भगवानपुर वार्ड नम्बर 03 गांधीनगर, दीपक पकरिया पिता स्व. चन्दु राम 43 वर्ष निवासी ग्राम खलिबा, खगेश राम पिता रामजतन 40 वर्ष, कोमल सिंह पिता बलिंदर सिंह 30 वर्ष, योगेन्द्र प्रसाद पिता शंकर प्रसाद 32 वर्ष, कार्तिक दास पिता स्व. नगेन्द्र दास 42 वर्ष, सभी निवासी चठिरमा थाना गांधीनगर, गोपाल भद पिता खितीश भद 25 वर्ष, निवासी संजयनगर आमापारा थाना जयनगर।

छह वर्षों में खंभा नहीं लगा, बांस के सहारे घरों तक पहुंचा विद्युत सप्लाई का तार

विभाग के जिम्मेदारों को बड़ी दुर्घटना का है इंतजार

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। सरकार जहां हर घर तक सुरक्षित बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं जिला मुख्यालय नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-8 केनापारा में यह दावा पूरी तरह खोखला नजर आ रहा है। यहां 4-5 परिवार पिछले लगभग 5-6 वर्षों से बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। घरों में बिजली का मीटर और वैध कनेक्शन होने के बावजूद आज तक बिजली के खंभे नहीं लगाए गए हैं। मजबूरी में लोग बांस की बल्लियों के सहारे लगभग 200 मीटर दूर से खिंचे बिजली के तार से खतरे के बीच अपने घरों को रौशन कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि खुले और लटकते बिजली के तार हर समय किसी बड़े हादसे को न्योता देते दिखाई देते हैं। पिछले वर्ष करंट की चपेट में आने से एक बकरी की मौत भी हो चुकी है, इसके बावजूद विभाग की नींद नहीं टूटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग ने कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि बिना खंभे के बिजली घरों तक कैसे सुरक्षित पहुंचेगी। मजबूरी में लोगों ने अपने खर्च पर बांस की बल्लियां खड़ी करके तार लगाया है, जो बरसात और तेज आंधी के दौरान कभी भी टूटकर सड़क पर गिर सकता है। यह रास्ता कई गलियों को जोड़ता है, जहां दिनभर लोगों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

ग्रामीणों का कहना है कि, इस संबंध में कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक न तो बिजली के खंभे लगाए गए और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। विडंबना है कि उपभोक्ता हर महीने नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक सुरक्षित बिजली सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। लोगों का कहना है कि यदि किसी दिन भारी वाहन गुजरते समय तारों की चपेट में आ गया या बारिश के दौरान तार टूटकर नीचे गिर गए, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी।

इधर, पूरे बलरामपुर नगर में लगातार हो रही बिजली की आंख-मिचौली से भी लोग परेशान हैं। बार-बार बिजली कटौती से व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि समाचार प्रकाशित होने के बाद बिजली विभाग हरकत में आता है या फिर वार्ड क्रमांक-8 के लोगों को इसी तरह बांस के सहारे अपनी जिंदगी और बिजली दोनों का जोखिम उठाना पड़ेगा।

घर में घुसकर मारपीट, महिला का मंगलसूत्र और डेढ़ लाख रुपये ले जाने का आरोप

छ.ग.फ्रंटलाइन शंकरगढ़। थाना क्षेत्र के ग्राम बचवार में घर में घुसकर मारपीट और दुकान का सामान क्षतिग्रस्त करके महिला सदस्य के गले से मंगलसूत्र छीनकर ले जाने व काउंटर से डेढ़ लाख रुपये गायब कर देने की शिकायत व्यवसायी ने पुलिस से की है। मामले में पुलिस ने 4 नामजद सहित अन्य के विरूद्ध बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बचवार निवासी मिथलेश कुमार गुप्ता 37 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि, 5 जुलाई रविवार को देर शाम करीब 8.41 बजे उसके पिता सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता ने फोन पर जानकारी दी कि उसके भाई अखिलेश को आशीष यादव फोन में धमकी भरे लहजे में तुम्हारे घर के पास आ रहा हूं, कहते हुये बाहर निकलने के लिये कह रहा है। जब वह घर के पास आया तो आशीष यादव, अभिषेक यादव सहित अन्य लोग घर के अंदर घुसे थे और उसके पिता सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता और मां सारो गुप्ता भी घर के अंदर मौजूद थे। सारो गुप्ता जमीन में गिरी हुई थी। आशीष यादव सहित अन्य लोग उसके भाई अखिलेश कुमार गुप्ता को घर में घुसकर खोज रहे थे। इसकी जानकारी वह राकेश कुमार गुप्ता को फोन करके दिया। घर के अंदर जाने पर आशीष यादव, अभिषेक यादव, रूपेश यादव, बृजेश यादव सहित अन्य लोग गाली-गलौज करते हुये हाथ, मुक्का और लात से मारपीट करने लगे। राकेश कुमार गुप्ता आया तो उसको भी सभी मारने लगे। मारपीट में दोनों को गंभीर चोटें आई है। आरोपियों ने इस दौरान दुकान का काफी सामान गिरा दिया और फेंक दिया। आरोप है कि, घटना के बाद आरोपी वृद्ध महिला सारो गुप्त का मंगलसूत्र छीनकर भाग गये। घर के अंदर काउंटर टूटा हुआ था और उसमें रखा 01 लाख 50 हजार रुपये भी नहीं था। मिथलेश कुमार गुप्ता की लिखित शिकायत पर शंकरगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 115(2), 191(2), 296, 304(2), 331(2), 332(ब), 351(2) का मामला दर्ज कर लिया है, और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर